Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 257
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 'अंतिम मील कनेक्टिविटी' के लिए नागरिकों की ...

4 चुनौती नहीं अवसर है ट्रंप की वीजा नीति,....

7 पाक क्रिकेटर हारिश रऊफ की शर्मनाक ...

नवरात्रि का दूसरा दिन

मां ब्रह्मचारिणी

चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र का हर दिन मां दुर्गा के विभिन्न नौ रूपों में से किसी न किसी एक रूप से संबंध रखता है। आज चैत्र नवरात्र के दूसरा दिन का संबंध मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी से है। आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। यहां 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ तपस्या से है और 'ब्रह्मचारिणी' का अर्थ है- तप का आचरण करने वाली। मां दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला है।

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व

सफेद वस्त्र धारण किये हुए मां ब्रह्मचारिणी के दो हाथों में से दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप-तप की शक्ति बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं आज जो भी व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर सकता है। इससे व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम करने के लिए मनोबल की भी बढ़ोतरी होती है।

मंत्र के जाप से प्रसन्न होंगी मां ब्रह्मचारिणी

अगर आप किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र इस प्रकार है- 'ऊं ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः'। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला, यानि 108 बार जाप करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही आज माता को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है । मंगल संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बड़ा ही लाभदायी होगा।

मां ब्रह्मचारिणी से जुड़ी पौराणिक कथा

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, नारद जी के उपदेश के बाद मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेलपत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। लिहाजा देवी मां हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं।

देश के नाम पीएम मोदी का खुला पत्र, बोले- आत्मनिर्भरता का आधार बनेंगे जीएसटी सुधार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार से लागू हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की एक बार फिर सराहना की है और कहा है कि ये सुधार बचत को बढ़ावा देंगे और समाज के हर वर्ग को सीधे तौर पर लाभान्वित करेंगे। देश के नाम एक खुले पत्र में, उन्होंने नवरात्रि के अवसर पर अपनी शुभकामनाएँ भी दीं और कहा कि इस त्योहार से भारत में 'जीएसटी बचत उत्सव' की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि ये सुधार देश के हर राज्य और क्षेत्र के 'विकास, निवेश को बढ़ावा देंगे और प्रगति को गति देंगे'। अपने पत्र में, उन्होंने यह भी कहा कि अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो जीएसटी स्लैब होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खाना-पीना, दवाइयाँ, साबुन, टूथपेस्ट, बीमा जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें और कई अन्य चीज़ें अब या तो कर-मुक्त होंगी या सबसे कम 5इ कर स्लैब में आ जाएँगी। जिन वस्तुओं पर पहले 12इ कर लगता था, वे लगभग पूरी तरह से 5इ कर स्लैब में आ गई हैं। उन्होंने आगे कहा, 'यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि

कई दुकानदार और व्यापारी 'तब और अब' के बोर्ड लगा रहे हैं, जो सुधारों से पहले और बाद के करों को दर्शाते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जो अब एक 'आकांक्षी नव-मध्यम वर्ग' बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आयकर में कटौती और अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी, जिससे अब देशवासियों के लिए अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना आसान हो जाएगा। जीएसटी के लिए अपनी सरकार की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने देश को 'आर्थिक रूप से' एकजुट किया है, जिससे 'एकरूपता' और 'राहत' आई है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने प्रणाली को सरल बनाया है और दरों को कम किया है, जिससे लोगों को अधिक बचत करने में मदद मिली है।

उन्होंने कहा, 'हमारे छोटे उद्योगों, दुकानदारों, व्यापारियों, उद्यमियों और एमएसएमई को भी व्यापार करने में आसानी और अनुपालन में आसानी होगी। कम कर, कम कीमतें और सरल नियमों का मतलब बेहतर बिक्री, कम अनुपालन बोझ और अवसरों में वृद्धि होगी, खासकर एमएसएमई क्षेत्र में।' अपने पत्र में, पीएम मोदी ने कहा कि देश का सामूहिक लक्ष्य 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश को आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और जीएसटी 2.0 देश को 'आत्मनिर्भर' बनने में मदद करेगा।

सांस्कृतिक निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौतीः प्रो. संजय द्विवेदी

भिलाई (छत्तीसगढ़)। भारतीय जन संचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी का कहना है कि गहरी सांस्कृतिक निरक्षरता और संवेदनहीनता ने समाज के सामने गंभीर संकट खड़े किए हैं, जिसमें मीडिया की विश्वसनीयता का मुद्दा भी शामिल है। सच के साथ खड़ा रहना कभी आसान नहीं था। किंतु समय ऐसे ही नायकों को इतिहास में दर्ज करता है, जो समाज का दर्द दूर करने के लिए सच के साथ खड़े होते हैं। वे यहां वसुंधरा संस्था द्वारा आयोजित 'भारतबोध, भारतीयता और हिंदी पत्रकारिता' विषय पर आयोजित संगोष्ठी को मुख्यवक्ता की आसंदी से संबोधित कर रहे थे।

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस संगोष्ठी में प्रतिष्ठित स्तंभकार श्री अनंत विजय, छत्तीसगढ़ साहित्य अकॉदमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विश्वेश ठाकरे अतिथि वक्ता के रूप में शामिल थे। प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का 200 सालों का इतिहास रचना, सृजन और संघर्ष का इतिहास है।

एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस, मलेशियाई कंपनी को नया समन जारी

नई दिल्ली। विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2006 में एयरसेल के अधिग्रहण के लिए उसकी सहायक कंपनी को दी गई एफआईपीबी मंजूरी के संबंध में सीबीआई के अनुरोध पर मलेशियाई दूरसंचार कंपनी मैक्सिस और उसके पूर्व निदेशक ऑगस्टस राल्फ मार्शल को नया समन जारी किया है। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने इस मामले के संबंध में मलेशियाई कंपनी एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क को भी समन जारी करने का अनुरोध किया था, जिसे विशेष अदालत ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मलेशिया में समन तामील करने के लिए अदालत से तीन महीने का समय मांगा है।

नामुमकिन को मुमकिन बनाने का माद्दा रखते हैं प्रधानमंत्री मोदीः उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग सहित दुनिया के तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोदी नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। प्रधानमंत्री के भाषणों की दो पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बावजूद, ट्रंप ने हमेशा मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसी तरह "अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मतभेदों के बावजूद" चीनी राष्ट्रपति के भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं।

उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम को

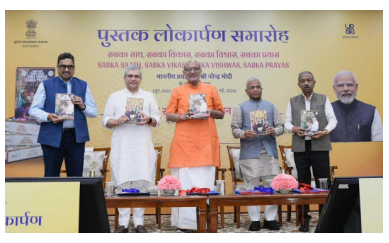

संबोधित करते हुए राधाकृष्णन ने कहा, "अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, लेकिन ट्रंप हमेशा कहते हैं कि मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं मोदी के खिलाफ हूं। वह हमेशा कहते हैं कि मैं मोदी के साथ हूं।" राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति (व्लादिमीर) पुतिन के भी बेहद अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा, "...साथ ही, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मतभेदों के बावजूद, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी मोदी जी के अच्छे मित्र हैं। यह हमने आज देखा है।" उपराष्ट्रपति ने कहा, "यही कारण है कि वह (प्रधानमंत्री मोदी) नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं।" मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के लिए सच्चे मन से काम करते हैं और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते।

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता की भाषा बोलते हैं और उन्हीं के लिए बोलते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले जब सरकारी योजनाएं शुरू होती थीं, तो वे 'बैंड-एड' (केवल तुरंत राहत) की तरह काम करती थीं। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए लोगों की सोच बदल दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी राजनीति का इस्तेमाल जनसेवा के लिए करते हैं और उनका हर फैसला समाज की भलाई को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

जीएसटी राहत पर सियासी घमासान

ममता बोलीं- केंद्र को श्रेय नहीं, हमें हुआ नुकसान

कोलकाता। संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के लागू होने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार की आलोचना की और कहा कि सारी राहत राज्य सरकारों के खजाने से आएगी, और केंद्र ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 25 पल्ली क्लब दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता। मैंने सबसे पहले पत्र लिखकर बीमा को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की थी। कई जीवन रक्षक दवाओं और छोटी वस्तुओं पर जीएसटी था। केंद्र सरकार ने इस राहत पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है; यह सब राज्य सरकारों के खजाने से आया है। वे श्रेय लेते हैं, लेकिन हमने इसकी कीमत चुकाई है।

ममता बनर्जी ने खुशी जताई कि लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन आरोप लगाया कि यह पैसा राज्य के जीएसटी हिस्से से काट लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्या वे हमारा पैसा लौटाएँगे? 100 दिनों के काम के लिए, आवास योजना

के लिए, सड़कों के लिए, जल स्वप्न के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिएः सब कुछ ठप पड़ा है। और अब, फिर से, 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं ऐसी परिस्थितियों में राज्य कैसे चलाऊँगी? फिर भी, मुझे खुशी है कि लोगों को लाभ होगा। लेकिन कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है; यह पैसा बस हमारे जीएसटी हिस्से से काट लिया गया है। तथाकथित 'डबल इंजन सरकार' चुपचाप इसे गुप्त रास्तों से वापस ले लेगी।

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने रविवार को अगले जीएसटी सुधारों की आलोचना की और केंद्र को जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए मजबूर करने का श्रेय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को दिया, जिसे उन्होंने पहले 'जनविरोधी' करार दिया था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए, घोष ने कहा, 'जीएसटी दरें वास्तव में जनविरोधी थीं... क्योंकि लोग उत्पाद का उपयोग करते हैं, इसलिए उस पर अधिक जीएसटी लगता है; स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अधिक जीएसटी लगता है। और जब सबसे अमीर लोग उत्पाद का उपयोग करते हैं, तो जीएसटी कम लगता है,' उन्होंने कहा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत आम के पौधे लगाए

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत अपने आवास पर आम के पौधे लगाए। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जारी 'सेवा पखवाड़ा' का हिस्सा है।

पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए, शर्मा ने कहा कि प्रदूषण कम करने और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राजस्थान को हरा-भरा, स्वस्थ और खुशहाल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित होकर, 'हरियालो राजस्थान' मिशन के तहत इस वर्ष राज्य में लगभग 11.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, "इस मिशन का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना है। पिछले वर्ष इस पहल के तहत 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे।

बिहार को मिली 9400 करोड़ की सौगात! सीएम ने किया जेपी गंगा पथ समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास

पटना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना जिला के दीघा में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 6495 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से पटना जिला अंतर्गत दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ) तक जे0पी0 गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण (लंबाई-35.65 कि0मी0) कार्य का शिलान्यास किया। जे0पी0 गंगापथ परियोजना के विस्तारीकरण कार्य पूर्ण होने से पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ (एन0एच0-922) तथा लखनऊ-गाजीपुर के बीच निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ (एन0एच0-319) से सम्पर्कता मिलेगी। साथ ही दानापुर-छितनावां-मनेर पथ (पुराना राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30) पर लगनेवाली जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना आने-जाने में भी काफी सहूलियत होगी। साथ ही बिहटा हवाई अड्डा आने-जाने में सुविधा होगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जे0पी0 गंगापथ का कोईलवर तक विस्तारीकरण कार्य आज से शुरू हो

गया है। निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूर्ण करें। इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने से शहरवासियों को आवागमन में और सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने दीघा से ही विभिन्न जिलों के 5 अन्य पथों जिनकी कुल लम्बाई 225.475 किलोमीटर है तथा जिनकी लागत 2 हजार 900 करोड़ रुपये है, का भी शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत 650 करोड़ 51 लाख की लागत से बांका, मुंगेर एवं भागलपुर जिला अंतर्गत धोरैया-इंगलिस मोड़ असरगंज पथ (लंबाई 58.47 कि0मी0) का निर्माण कार्य, 814 करोड़ 22 लाख की लागत से मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत हथौड़ी-औराई पथ में एक उच्च स्तरीय पुल (लंबाई- 21.3 कि0मी0) का पहुंच पथ सहित निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। साथ ही 373 करोड़ 56 लाख की लागत से भोजपुर जिला अंतर्गत आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ (लंबाई 32.26 कि0मी0) के निर्माण कार्य, 701 करोड़ 26 लाख की लागत से छपरा एवं सीवान जिला अंतर्गत छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ (लंबाई-72.18 कि0मी0) के निर्माण कार्य तथा 361 करोड़ 32 लाख की लागत से नवादा, नालंदा एवं गयाजी जिला अंतर्गत बनगंगा-जेठियन-गहलौत बिन्दस पथ (लंबाई 41.25 कि0मी0) के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।

दशहरा उद्घाटन पर सियासत!

सिद्धारमैया ने विरोधियों को घेरा, कहा- दशहरा किसी एक धर्म का त्योहार नहीं है

बैंगलुरू। बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक द्वारा मैसूर दशहरा 2025 के उद्घाटन और कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उठाई गई कई आपत्तियों के बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि दशहरा राज्य के सभी लोगों का त्योहार है; यह किसी एक धर्म या जाति का त्योहार नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बानू मुश्ताक, एक मुस्लिम महिला होने के बावजूद, एक कन्नड़ कवि और लेखिका हैं। उन्होंने कन्नड़ साहित्य को सम्मान दिलाया है। परंपरा के अनुसार, इस वर्ष दशहरा 11 दिनों तक मनाया जा रहा है। राज्य में अच्छी बारिश हुई है और लोग मुस्कुरा रहे हैं। जंबू सवारी की विशेष भव्यता होगी। गारंटी योजनाएँ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लागू नहीं की जाती हैं। सिद्धारमैया ने सवाल किया कि क्या भाजपा या जद (एस) इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं? ये योजनाएँ सभी लोगों के लिए हैं। कन्नड़ कवि कुवेम्पु ने कहा कि व्यक्ति को मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिदों से ऊपर उठना चाहिए। समाज को धर्म या जाति के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। दशहरा राज्य

के सभी लोगों का त्योहार है। यह किसी एक धर्म या जाति का त्योहार नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं का समर्थन किया और विपक्ष से पूछा कि क्या राज्य दिवालिया हो गया है।

मोदी को अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में बात करनी चाहिए थीः फारूक

श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की बात करनी चाहिए थी। मोदी ने रविवार शाम अपने संबोधन में लोगों को जीएसटी सुधार के फायदे बताए। संशोधित जीएसटी दरें सोमवार से लागू हुईं। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, "आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, अच्छा होता अगर आपने (मोदी) अपने संबोधन में हमारे राज्य के दर्जे पर बात की होती।" जब उनसे पूछा गया कि क्या नेकां को उच्चतम न्यायालय से अनुकूल फैसले की उम्मीद है, तो अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का हर नागरिक राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीद लगाए बैठा है। राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर याचिका अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। उन्होंने कहा, "सिर्फ नेशनल कांफ्रेंस ही नहीं, बल्कि सभी को उम्मीद है कि हमें फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा।" जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के अध्यक्ष यासीन मलिक के मुकदमे से संबंधित एक सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि

यह अदालत का विषय है। उन्होंने कहा, "फैसला अदालत करती है। अदालत ही तय करेगी। हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है।" मलिक को फरवरी 2019 में गिरफ्तार किया गया था और वह आतंकवाद को वित्तपोषित करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उस पर कई मामले लंबित हैं, जिनमें 1990 में रुबैया सईद के अपहरण और रावलपोरा में वायुसेना के कर्मियों पर हमले का मामला भी शामिल है।

अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में शासन व्यवस्था को "उस्तरे की धार पर चलने जैसा" करार दिया। उन्होंने कहा, "...लेकिन हमें उस पर चलना है और पीछे नहीं हटना है।" डोडा से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि विधायक द्वारा इस्तेमाल की गई अनुचित थी, लेकिन उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तार करना भी गलत था।

उन्होंने कहा, "मलिक द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द अनुचित थे, लेकिन पीएसए लगाना (भी) गलत था। इसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।" उन्होंने कहा कि निर्वाचित सरकार के पास पीएसए हटाने का अधिकार नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा, "हमारे पास यह अधिकार नहीं है, यह उपराज्यपाल के पास है।

भारत को ट्रंप सरकार के आगे नहीं झुकना चाहिएः एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के आगे झुकना नहीं चाहिए।

ओवैसी ने ट्रंप प्रशासन द्वारा एच1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका असर भारतीयों पर पड़ेगा क्योंकि इस तरह के वीजा धारकों में लगभग 71 प्रतिशत भारतीय नागरिक हैं और इनमें से अधिकांश लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहता। लेकिन मोदी सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख ने ट्रंप के साथ रात्रिभोज किया और हम अपने पड़ोसी देश को अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करते हुए भी देख रहे हैं। इस घटनाक्रम का क्या मतलब है?'

हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ने संवाददाताओं से कहा, 'अगर हम इन पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो हमारे

बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें ट्रंप सरकार के आगे बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए।'

उन्होंने पूछा कि 'हाउडी मोदी' और ट्रंप समर्थक अन्य कार्यक्रमों की क्या उपलब्धि है? ओवैसी ने कहा कि यह जरूरी है कि भारत को डॉलर-विमुद्रीकरण के बाद रुपये में व्यापार समझौते करने चाहिए।

मुंबई में दुर्गा प्रतिमा खंडित, गरमाया माहौल! दो गुटों में झड़प के बाद 7 गिरफ्तार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई के मानखुर्द में देवी दुर्गा की प्रतिमा कथित तौर पर खंडित होने के बाद दो समूहों में झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप तनाव फैल गया और पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया। यह घटना नवरात्रि की पूर्व संध्या पर हुई, जब एक समूह ने प्रतिमा खंडित पाई और दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि मुंबई में देवी दुर्गा की एक मूर्ति को कथित तौर पर अपवित्र किए जाने के बाद तनाव बढ़ गया, जिसके बाद दो समूहों के बीच झड़प हो गई। उन्होंने बताया कि रविवार रात मानखुर्द इलाके में हुई इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई में दुर्गा प्रतिमा खंडित! तनाव फैला पुलिस के अनुसार, मानखुर्द पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नवरात्र की पूर्व संध्या पर देवी की प्रतिमा को एक संकरी गली से ले जाया जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने पाया कि प्रतिमा खंडित है तथा इसके लिए दूसरे समूह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके साथ बहस शुरू कर दी।

दो गुटों में झड़प के बाद 7 गिरफ्तार अधिकारी ने बताया कि दोनों समूहों के बीच झड़प हुई और उन्होंने एक-दूसरे पर हमला किया। बाद में, पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार सात लोगों के खिलाफ मारपीट और गैरकानूनी रूप से एकत्र होने सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संबंधित समूह हर साल नवरात्र उत्सव मनाता है। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच जारी है।

लोअर परेल स्थित बेनिफिट बिज़नेस हाउस द्वारा विभिन्न अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया

बृहन्मुंबई नगर निगम के जी (दक्षिण) प्रभाग द्वारा की गई कार्रवाई

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) लोअर परेल स्थित बेनिफिट बिज़नेस हाउस के विरुद्ध बीएमसी द्वारा निर्धारित फ्लोर एरिया इंडेक्स (एफएसआई) का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से अतिरिक्त निर्माण करने के आरोप में बेदखली की कार्रवाई कर रहा है। बीएमसी के जी (दक्षिण) प्रभाग द्वारा की जा रही इस कार्रवाई में, बेनिफिट बिज़नेस हाउस में एक अनधिकृत निर्माण को बेदखल किया गया है। इस बीच, दो अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने का कार्य जारी है।

नगर आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में, बृहन्मुंबई क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में, उपायुक्त (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले, सहायक आयुक्त, जी (दक्षिण) प्रभाग स्वप्नजा क्षीरसागर।

इस संदर्भ में, लोअर परेल के एन.एम. जोशी रोड स्थित बेनिफिट बिज़नेस हाउस में विभिन्न अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा निर्धारित फ्लोर एरिया इंडेक्स (एफएसआई) का उल्लंघन करते हुए, बेनिफिट बिज़नेस हाउस में तीन स्थानों पर अनधिकृत अतिरिक्त निर्माण किए गए थे। इसमें यूनिट संख्या 1सी के पूर्वी तल पर 210.8 वर्ग मीटर, यूनिट संख्या 3ए और 4ए पर 260 वर्ग मीटर और यूनिट संख्या 3सी और 4सी पर 166 वर्ग मीटर का अनधिकृत निर्माण किया गया था।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के जी (दक्षिण) ज़ोन के भवन एवं कारखाना विभाग ने 16 से 19 सितंबर, 2025 तक यूनिट संख्या 1सी में अनधिकृत निर्माणों को हटा दिया है। इस बीच, यूनिट संख्या 3ए और 4ए के साथ-साथ यूनिट संख्या 3सी और 4सी में भी तोड़फोड़ की प्रक्रिया जारी है।

इस बीच, महानगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

'एक पेड़ माँ के नाम' - स्वच्छता ही सेवा 2025 के अंतर्गत सोलापुर और कलबुरगि में सोलापुर मंडल का पौधारोपण अभियान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने चल रहे स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत 21 सितंबर 2025 को 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल के अंतर्गत पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में महिला कर्मचारियों और मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, सोलापुर मंडल की सदस्याओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस सार्थक पहल में, लगभग 40 महिला प्रतिभागियों ने तीन स्थानों - बाल विकास मंदिर स्कूल, सोलापुर; रेलवे अस्पताल, सोलापुर और कलबुरगि रेलवे स्टेशन पर एरिका पाम, बॉटल पाम, मोरपंखी, चमेली और गुलाब सहित 90 पौधे लगाए।

'एक पेड़ माँ के नाम' की अवधारणा माताओं के प्रति सम्मान की भावना को एक हरे-भरे कल के लिए पेड़ों की देखभाल की ज़िम्मेदारी से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस कार्यक्रम में CRWWO के

पदाधिकारियों - निभा कुमारी, अध्यक्षा; पल्लवी गनेर, सचिव; श्रीमती सपना बनसोडे, कोषाध्यक्ष; सुमन साहू; श्रीमती सरोज भोसले और अन्य - की गरिमामयी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी देखी गई। CRWWO की सदस्याओं और महिला कर्मचारियों ने इस नेक कार्य में हाथ मिलाया, जो पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की सशक्त भूमिका का प्रतीक है।

पौधारोपण गतिविधि का संचालन और समन्वयन सोलापुर मंडल के सहायक मंडल इंजीनियर (ट्रैक) काकासाहेब भोसले द्वारा सुचारु रूप से किया गया, जिसमें विजयकुमार खामगांवकर, जितेंद्र वाघमारे और कपिल इंगोले की समर्पित टीम का बहुमूल्य सहयोग रहा।

यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देती है, बल्कि परिवार और प्रकृति दोनों के प्रति जिम्मेदारी, देखभाल और समर्पण का संदेश भी फैलाती है। मध्य रेल का सोलापुर मंडल सतत विकास, जनभागीदारी और स्वच्छता ही सेवा की भावना के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे के 12 कर्मचारियों को महाप्रबंधक सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में 12 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षित रेल संचालन संभव हुआ। इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर उनकी सतर्कता और अगस्त, 2025 के दौरान अप्रिय घटनाओं को रोकने और इस प्रकार रेल संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इन 12 कर्मचारियों में से 2-2 कर्मचारी मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर मंडल से हैं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, श्री गुप्ता ने सम्मानित होने वाले कर्मचारियों की सतर्कता की सराहना की और कहा कि वे सभी के लिए अनुकरणीय आदर्श हैं। सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे टूटे हुए बोल्ट का पता लगाना, कोच/इंजन के नीचे धुएँ और चिंगारी का पता लगाना, ट्रैक में दरार, टूटी हुई कपलर बॉडी, वैगनों और दुर्घटना राहत ट्रेन (एआरटी) में लटकती वस्तुओं का पता लगाना, किसी खुले लेवल क्रॉस गेट से पहले आपातकालीन ब्रेक लगाकर अप्रिय घटनाओं को रोकना आदि में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के प्रति कर्मचारियों की उच्च स्तर की प्रतिबद्धता और समर्पण।पश्चिम रेलवे सभी पुरस्कृत कर्मचारियों की उनकी त्वरित सोच और सतर्कता के लिए सराहना करता है, जिसने अप्रिय घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एनएमयूएमपीए जिला स्तरीय शालेय तैराकी प्रतियोगिता का आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने उत्साहपूर्वक उद्घाटन किया

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तैराक शुभम वनमाली की विशेष उपस्थिति

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई शहर से अच्छे तैराक तैयार करने के उद्देश्य से, नवी मुंबई नगर निगम ने एक ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल उपलब्ध कराया है और इसके माध्यम से नवी मुंबई के तैराकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने की शुभकामनाएँ देते हुए, नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने कहा कि नवी मुंबई नगर निगम सभी खेलों में उच्च गुणवत्ता वाली खेल सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।

नवी मुंबई नगर निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत खेल एवं युवा सेवा निदेशालय, ठाणे जिला क्रीड़ा परिषद के सहयोग से वाशी स्थित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल में आयोजित 'एनएमएमपीए जिला स्तरीय शालेय 'तैराकी' प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर आयुक्त ने उपस्थित लोगों से बातचीत की। इस अवसर पर खेल एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की उपायुक्त श्री अभिलाषा पाटिल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के उपायुक्त डॉ. अजय गाडे, वाशी संभाग के संयुक्त आयुक्त श्री सुखदेव येदवे, क्रीड़ा अधिकारी श्री. रेवप्पा गुरव उपस्थित थे।

इस अवसर पर, केंद्र सरकार के तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध समुद्री तैराक और स्वच्छ नवी मुंबई मिशन के युवा प्रतीक, श्री शुभम वनमाली उपस्थित थे। उनके साथ, ठाणे जिला तैराकी संघ के सचिव श्री कैलाश अखाड़े, शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता तैराक श्री गोकुल कामथ और नामुम्पा जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आयोजन समिति के सदस्य श्री धनंजय वनमाली भी उपस्थित थे। इस पहल के माध्यम से, 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया।

इस प्रतियोगिता में नगर निगम क्षेत्र के 31 निजी और नगरपालिका स्कूलों के 200 से अधिक तैराकों ने भाग लिया। विभिन्न आयु वर्ग और दूरी की इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों और अभिभावकों की भारी उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए, तैराक श्री शुभम वनमाली ने समुद्र में तैरने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बढ़ते तापमान और समुद्र में कचरे की समस्या का उल्लेख करते हुए, समुद्र में तैरते समय किसी भी प्रकार का कचरा न फेंकने की अपील की। नवी मुंबई नगर निगम खिलाड़ियों के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों और छात्रों से अपील की कि वे सभी खेलों में तैराकों और खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएँ। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है और उन्हें इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और स्वच्छता और नवी मुंबई शहर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए।

खेल विभाग की उपायुक्त श्री अभिलाषा म्हात्रे ने बताया कि एनएमयूएमपीए की जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताएँ 4 सितंबर से शुरू हो गई हैं और इस वर्ष 48 खेल प्रतियोगिताओं में छात्रों की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दीं।

सफाईमित्र सुरक्षा शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार पर विशेष प्रशिक्षण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें स्वच्छता अभियानों के साथ-साथ सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में, पूर्व में आयोजित सफाईमित्र स्वास्थ्य शिविरों की तरह, आज नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय स्थित ज्ञान केंद्र में 'सफाईमित्र सुरक्षा शिविर' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इसमें नवी मुंबई महानगरपालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और सीपीआर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत एक धर्मार्थ संस्था, अनुभव की ओर से आधार एबिलिटी फाउंडेशन के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसमें 200 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया और आपातकालीन चिकित्सा सहायता पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। आधार एबिलिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. नितिन राठौड़ की उपस्थिति में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेथे द्वारा प्रतिभागी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

सफाईमित्र सुरक्षा शिविर में स्वास्थ्य प्रशिक्षण का उद्घाटन अतिरिक्त नगर अभियंता श्री अरविंद शिंदे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के उपायुक्त डॉ. अजय गाडे, उपायुक्त डॉ. अमोल पलावे की उपस्थिति में हुआ। इस प्रशिक्षण में दी गई जानकारी बहुत उपयोगी है और यहाँ सीखी गई बातें आपातकालीन चिकित्सा समस्याओं के समय अमल में लाने पर किसी की जान बचा सकती हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रशिक्षण को गंभीरता और पूर्ण ध्यान से लेने की भी अपील की। आधार एबिलिटी फाउंडेशन की डॉ. सोनल सिंह और डॉ. विनीता सूर्यवंशी ने उपस्थित सफाई कर्मचारियों से बातचीत की ।

मध्य रेल

विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (क.च. स्टॉक) मध्य रेल विद्युत लोको शेड कल्याण 421301, प्रतिष्ठित ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यो/ सर्विसेज के लिए खुली ई-निविदा वेबसाईट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से आमंत्रित करते है। **कार्य का विवरण:** लिफ्टिंग टैकल, ईओटी क्रेन, स्टील वायर रोप स्लिंग्स एवं चेन स्लिंग्स का निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन, फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 28, 29 एवं 31 के अंतर्गत, प्रमाण पत्र की तीन वर्षों के लिए प्रस्तुति सहित। **कार्य की औसत लागत:** ₹ 17,62,145.73 (जी. एस. टी सहित)। **ई.एम.डी./बिड सिक्योरिटी:** ₹ 35,300/-. **निविदा पत्र का मूल्य:** NIL. **समापन/अनुरक्षण अवधि:** 36 Months. **अनुदेश: 1)** उपरोक्त निविदा की बंद होने की तिथि एवं समय **10/10/2025** को **11.00 बजे** और उसी दिन **11.00 बजे** के बाद खोली जाएगी। निविदा ऑफर की वैधता 60 दिन है। **2)** निविदा का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं। सम्पूर्ण विवरण वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (क.च. स्टॉक) मध्य रेल विद्युत लोको शेड कल्याण 421301 के कार्यालय में भी उपलब्ध हैं।

निविदा संख्या: ELSKYN/WKS/2025/19/ Safety Sling दि. 18/09/2025

असुरक्षित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना दंडनीय अपराध है

Sai/480

भुसावल मंडल में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत 'रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल' प्रदर्शनी का आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भुसावल मंडल ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत 'रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल' प्रदर्शनी का आयोजन किया। मंडल रेल प्रबंधक भुसावल के मार्गदर्शन में, भुसावल मंडल कार्यालय में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें रिसाइकिल की गई सामग्रियों से बने अभिनव उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

इस प्रदर्शनी में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर बनाए गए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को दर्शाया गया है। विद्युत लोको शेड और बेसिक ट्रेनिंग सेंटर (बीटीसी) भुसावल के कर्मचारियों ने अपने कौशल का उपयोग करके इन उत्पादों को तैयार किया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य न केवल लोगों को रिसाइक्लिंग के महत्व के बारे में जागरूक करना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि कैसे साधारण वस्तुओं का उपयोग कर अभिनव रचनाएँ बनाई जा सकती हैं। 'रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल' का मंत्र न केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता

है, बल्कि यह हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक हरित और स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करने का भी एक तरीका है।

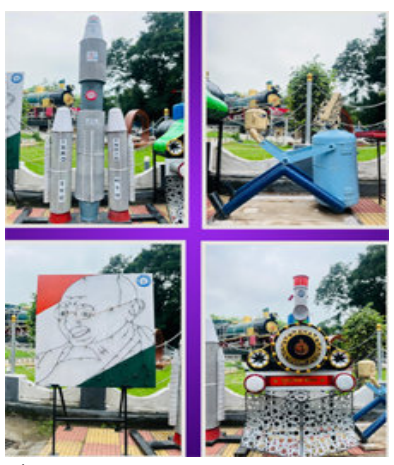

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर प्रतिभा प्रतियोगिताओं का आयोजन - सहभागिता का आह्वान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई नगर निगम बुजुर्गों के प्रति अपने स्नेह के लिए जाना जाता है और नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में बुजुर्गों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर बुजुर्गों को उनके अंतर्निहित गुणों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतिभा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक दिवस के लिए एक विशेष कार्यक्रम 1 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जा रहा है और उससे पहले विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

इसमें कहानी सुनाना, हास्य, वेशभूषा, नृत्य (व्यक्तिगत), टेलीफोन नामक पांच प्रतियोगिताएं 25 सितंबर 2025 को सुबह 9.30 बजे महात्मा फुले भवन, सेक्टर 03, वाशी में आयोजित की जाएंगी और आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है। साथ ही, समूह नाटक, एकालाप अभिनय, गायन (व्यक्तिगत), कविता पाठ की प्रतियोगिताएं 26 सितंबर 2025 को सुबह 9.30 बजे महात्मा फुले भवन, सेक्टर 03, वाशी में आयोजित की जाएंगी और आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है।

ब्रीज़ गेम प्रतियोगिता 26 सितंबर 2025 को सुबह 9.30 बजे वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र, नागा गण पाटिल उद्यान, सेक्टर 03, वाशी में आयोजित की जाएगी। 15, सीबीडी बेलापुर में आयोजित किया जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 है। कैरम प्रतियोगिता (एकल और युगल) और शतरंज प्रतियोगिता 29 सितंबर 2025 को सुबह 9.30 बजे वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र, स्वर्गीय सीताराम मास्टर उदयन, सेक्टर 7, संपदा में आयोजित की जाएगी और आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 है।

निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, 'जीवन सुंदर है... जीना सीखें' विषय पर निबंध आवेदन के साथ 26 सितंबर, 2025 तक जमा करने होंगे।

डाक पत्र लेखन प्रतियोगिता में, परिवार के एक सदस्य को 'पत्र' विषय पर एक पत्र आवेदन के साथ 26 सितंबर, 2025 तक जमा करना होगा।

1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही उन वरिष्ठ नागरिक दम्पतियों को भी सम्मानित किया जाएगा जिनके विवाह के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जिनके लिए आवेदन 26 सितंबर 2025 तक जमा करने होंगे।

इन सभी प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें और आवेदन पत्र नगर निगम के सभी विभागीय कार्यालयों के साथ-साथ सामाजिक विकास विभाग, नवी मुंबई नगर निगम बेलापुर भवन कार्यालय, प्रथम तल, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर में सरकारी छुट्टियों को छोड़कर उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार, ये नवी मुंबई नगर निगम के वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र में भी उपलब्ध हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बेलापुर मंडल - मिथुन म्हात्रे: 9867231403, नेरुल मंडल - प्रियंका पाटिल: 9082311440, वाशी मंडल - सुंदर परदेशी: 9594841666, कोपरखैरणे और घनसोली मंडल - दादासाहेब भोसले: 9372106976 और ऐरोली और दीघा मंडल - दशरथ गंभीरे: 9702309054 से संपर्क करें।

यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशी का त्योहार है, और नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे सभी से अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में भाग लेने और इन गतिविधियों को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं।

मध्य रेल

एलएचबी एनएसी कोचों की साज-सज्जा

कार्य का विवरण: एलएचबी एनएसी कोचों की साज-सज्जा। **अनुमानित लागत:** ₹ 2,35,63,320.25. **निविदा प्रपत्र का शुल्क:** ₹ -. **ईएमडी:** ₹ 2,67,800/-. **समापन अवधी:** 12 माह। वे प्रतिष्ठान जो उनकी व्यक्तीगत क्षमता मे न्यूनतम योग्यता मापदंड की पूर्तता करते हों उनसे ही यह ई-निविदा आमंत्रित की गयी है ई-निविदा की जमा करने की तिथी एवं अवधि दि. **10/10/2025** को **17.00** बजे तक है। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी रेल की आधिकारीक वेबसाइट: **https://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

खुली ई-निविदा सूचना संख्या: PR-C-LHB-FUR-25-26-723A दि. 15/09/2025

असुरक्षित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना दंडनीय अपराध है

Sai/478

परिवहन सेवा में अगला कदम 'पॉड टैक्सी'

'अंतिम मील कनेक्टिविटी' के लिए नागरिकों की सेवा में पॉड टैक्सी सेवा लाई जानी चाहिए- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों का विस्तार हो रहा है। नागरिकों को काम पर जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मज़बूत करने के साथ-साथ नागरिकों को 'अंतिम मील कनेक्टिविटी' प्रदान करना भी ज़रूरी है। परिवहन सेवा में अगला कदम 'पॉड टैक्सी' है और 'अंतिम मील कनेक्टिविटी' के लिए इस सेवा को नागरिकों की सेवा में लाया जाना चाहिए, यह निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सह्याद्री अतिथि गृह में पॉड टैक्सी के संबंध में आयोजित एक बैठक में दिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कुर्ला और बांद्रा रेलवे स्टेशन के बीच 'व्यावसायिक क्षेत्र' में यह सेवा महत्वपूर्ण होगी। इस स्थान पर भविष्य में बनने वाला बुलेट ट्रेन स्टेशन और मुंबई उच्च न्यायालय इस क्षेत्र के नागरिकों के आवागमन को बढ़ाएगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि इससे मौजूदा

परिवहन सेवा पर दबाव बढ़ेगा और नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में, पॉड टैक्सी इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए बिना किसी देरी और आसानी से परिवहन सेवाएँ प्राप्त करने का एक विकल्प होगी। मुंबई में एक ही कार्ड के माध्यम से सभी परिवहन सेवाओं में यात्रा की सुविधा प्रदान करने हेतु एक प्रणाली बनाई जा रही है। नागरिक भी इसी कार्ड के माध्यम से पॉड टैक्सी सेवाओं का लाभ उठा सकें, इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। कुर्ला और बांद्रा स्टेशन क्षेत्रों को पॉड टैक्सियों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। कुर्ला स्टेशन क्षेत्र में पुलिस आवास स्थान के बजाय, उसी क्षेत्र में पुलिस को स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र की इमारतों को इन पॉड टैक्सियों के माध्यम से स्टेशन से जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा। इस क्षेत्र के व्यावसायिक महत्व को देखते हुए, विश्वस्तरीय सेवा सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अवसर पर यह भी सुझाव दिया कि स्टेशन के बाहर स्काईवॉक का और अधिक उपयोग करने के लिए अच्छी अवधारणाओं को लागू किया जाना चाहिए। बैठक में बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) असीम कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव (गृह) अनूप कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी और पुलिस आयुक्त भारती ने प्रस्तुतियाँ दीं।

स्वच्छता ही सेवा 2025 - मुंबई मंडल ने छठे दिन 'रिड्यूस, रियूज, रिसायकल ' को बढ़ावा दिया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पर्यावरणीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण पहलू 'रीड्यूस, रियूज और रिसाकल करें' के सिद्धांत को अपनाना है। चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत, छठा दिन इस महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित था।

मध्य रेल मुख्यालय में, मुंबई मंडल के सहयोग से, 'वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट' बनाने की रचनात्मक संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। परिचालन विभाग की मुख्य कार्यालय अधीक्षक ने अपनी अभिनव कलाकृतियाँ प्रदर्शित कीं, जिनमें बोतल कला, एक्सपायर हो चुके टिशू पेपर से बने फूल और बेकार सीपों और मोतियों से बने आभूषण शामिल थे।

इस पहल में आगे बढ़ते हुए, अरमान प्लास्टिक्स ने बेकार प्लास्टिक से बने उत्पादों की एक अनूठी श्रृंखला प्रदर्शित की, जिसमें बताया गया कि कैसे रीसाइक्लिंग कचरे को उपयोगी वस्तुओं में बदल सकती है। उनके प्रदर्शन में टेडी बियर, टी-शर्ट और बेकार प्लास्टिक के पैकेट्स से प्रसंस्कृत फाइबर से बने अन्य उत्पाद शामिल थे। उन्होंने पीवीसी पाइप बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मिल्क बैग के पैकेट का भी प्रदर्शन किया और बताया कि कैसे रीसाइक्लिंग से पर्यावरणीय खतरों को कम किया जा सकता है।

'वेस्ट टू वेल्थ' गतिविधि ने 3R - रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल - को लागू करने के महत्व पर एक सशक्त संदेश दिया, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को न्यूनतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लोक नाट्य और तमाशा के नामों में परिवर्तन का प्रस्ताव समिति के समक्ष-मंत्री आशीष शेलार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई।संगीतबाड़ी कला केंद्र के लिए लोकनाट्य/तमाशा नाम का प्रयोग न करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। तमाशा कलाकार संघ का प्रस्ताव पूर्व में गठित समिति को भेजा जाए। यह समिति अगले 15 दिनों के भीतर कला केंद्र और तमाशा के नाम में परिवर्तन के सुझाव पर निर्णय दे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने निर्देश दिया।

तमाशा कलाकारों के विभिन्न मुद्दों पर आज मंत्री एडवोकेट शेलार की अध्यक्षता में पी. एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी में एक बैठक हुई। सांस्कृतिक कार्य विभाग के निदेशक विभीषण चावरे, गृह विभाग के उप सचिव ए.एन. इस बैठक में सखारकर, अवर सचिव बालासाहेब सावंत, अखिल भारतीय लोक कलाकार मराठी तमाशा परिषद के अध्यक्ष संभाजीराजे जाधव, सलाहकार खंडूराज गायकवाड, आविष्कार मुले, किरण कुमार धवलपुरीकर, रघुवीर खेडकर, शेषराव

गोपाल, आनंद भिसे, सुनील वाडेकर उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने राज्य में तमाशा और कलाकेंद्र कलाकारों की विभिन्न शिकायतों के निवारण के लिए दो अलग-अलग समितियों के गठन का निर्णय लिया है। मंत्री एडवोकेट शेलार ने कहा कि यह समिति इस समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने और इसका नाम बदलने के उपाय सुझाएगी। साथ ही, इन लोक कलाकारों को गाँवों में कला प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न अनुमतियों की आवश्यकता होती है। मंत्री एडवोकेट शेलार ने निर्देश दिया कि यह नियुक्त समिति इस संबंध में उपाय सुझाए और अगले 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आयोजित वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी में रीसाइक्लिंग की अभिनव प्रस्तुतियाँ

कचरे को बहुमूल्य चीजों में बदला - पश्चिम रेलवे ने अभिनव रीसाइक्लिंग से यात्रियों को दी प्रेरणा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा 22 सितंबर 2025 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक अनूठी 'वेस्ट टू आर्ट' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत स्टेशन के कॉन्कोर्स हॉल में आयोजित यह प्रदर्शनी दिखाती है कि पश्चिम रेलवे अपशिष्ट कम करने और बेकार सामग्रियों के रचनात्मक पुनः उपयोग के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। यह पहल यह भी संदेश देती है कि आमतौर पर बेकार मानी जाने वाली वस्तुएँ भी सृजनात्मकता और नवप्रवर्तन से उपयोगी, आकर्षक और प्रेरक रूप ले सकती हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस प्रदर्शनी में मूर्तियों और कलात्मक प्रतिष्ठानों का एक प्रभावशाली संग्रह प्रदर्शित किया गया है, जो पूरी तरह से कबाड़ और बेकार रेलवे सामग्री से निर्मित हैं। एमएस पाइप, एंकर लिंक कंट्रोल आर्म्स, एमएस एंगल्स, एमएस शीट्स, ब्रेक हैंगर ब्रैकेट्स, कॉइल्ड स्प्रिंग्स, अल्टरनेटर टेंशन रॉड स्प्रिंग्स, वॉशर और अन्य धातु के स्क्रैप जैसी वस्तुएँ, जिन्हें आमतौर पर कबाड़खाने में फेंक दिया जाता है, उन्हें कला की आकर्षक कृतियों में बदल दिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा संचालित यह पहल न केवल रचनात्मकता के लिए है, बल्कि जागरूकता फैलाने के लिए भी है। हर स्थापना एक संदेश देती हैः कचरे पर पुनर्विचार करें, स्मार्ट तरीके से रीसायकल करें और नई संभावनाओं की कल्पना करें। मुंबई सेंट्रल से रोज़ाना गुज़रने वाले हज़ारों यात्री इस प्रदर्शन को निहारने, तस्वीरें लेने और 'कचरे' के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ लौटते हैं।

श्री विनीत अभिषेक ने आगे बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से, पश्चिम रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को उन चीज़ों में छिपी संभावनाओं को देखने के लिए प्रेरित करना है, जिन्हें आमतौर पर कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पहल एक छोटा लेकिन सार्थक कदम है जो स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप है और एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भविष्य के निर्माण के पश्चिम रेलवे के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

जालना में ओबीसी कार्यकर्ता की कार को लगाई गई आग, मनोज जरांगे के समर्थकों पर लगा आरोप

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

जालना।आरक्षण पर विवाद के बीच महाराष्ट्र के जालना जिले में एक अज्ञात व्यक्ति ने ओबीसी कार्यकर्ता की कार में आग लगा दी। यह घटना रविवार रात करीब दस बजे नीलम नगर इलाके में हुई। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक व्यक्ति बोतल से ज्वलनशील पदार्थ कार पर डालता है और फिर उसमें आग लगा देता है। यह कार ओबीसी कार्यकर्ता नवनाथ वाघमारे की थी, जो वहां खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने समय पर पहुंचकर आग बुझा दी और कार को पूरी तरह से जलने से बचा लिया। कार का ऊपरी हिस्सा ही जला।

बाद में मीडिया से बातचीत में वाघमारे ने आरोप लगाया कि यह काम मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के समर्थकों ने किया है। मनोज जरांगे भी जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव के रहने वाले हैं। वाघमारे ने कदीम जालना थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

वाघमारे ने कहा, मेरी कार को जानबूझकर जलाया गया। स्थानीय लोगों ने आग फैलने से पहले उसे बचा लिया। हम संविधान को मानते हैं, न कि ऐसे हिंसक रास्तों पर चलते हैं। सोचिए, अगर ओबीसी कार्यकर्ताओं ने जरांगे की कार जला दी होती तो क्या होता? उन्होंने फिर अपना आरोप दोहराया कि इसघटना के पीछे जरांगे के समर्थकों का हाथ है। उन्होंने पुलिस से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

आरक्षण को लेकर संघर्ष का केंद्र बना जालना

जालना जिला इस समय मराठा, ओबीसी, धनगर और बंजारा समुदायों के बीच आरक्षण को लेकर संघर्ष का केंद्र बन गया है। ओबीसी कार्यकर्ता हैदराबाद गजट को लागू करने का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र देकर उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की योजना बनाई गई है। ओबीसी समूहों का कहना है कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पहले से आरक्षण पाए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अवसर कम हो जाएंगे।

बंजारा और धनगर समुदाय ने भी तेज की मांग

पिछले हफ्ते बंजारा समुदाय ने खुद को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फिलहाल बंजारा को विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति (वीजेएनटी) श्रेणी के तहत तीन फीसदी आरक्षण मिलता है। वहीं, धनगर समुदाय के कार्यकर्ता दीपक बोरहडे पिछले छह दिनों से जालना में आमरण अनशन पर हैं। उनकी भी मांग यही है कि धनगरों को एसटी श्रेणी में शामिल किया जाए।

मराठा समुदाय के लिए जरांगे का आंदोलन

मनोज जरांगे कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं और मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने की मांग कर चुके हैं। इसी के जवाब में राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि मराठवाड़ा के वे मराठा लोग जो अपने कुनबी जाति का प्रमाण दे सकें, उन्हें ओबीसी प्रमाणपत्र दिया जाएगा, ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके।

पुरस्कार विजेता शिक्षक राज्य के ब्रांड एंबेसडर हैं- उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

गणमान्य व्यक्तियों द्वारा क्रांतिज्योति सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। शिक्षकों का दायित्व छात्रों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। इसलिए शिक्षकों का सम्मान राष्ट्र निर्माण का सम्मान है। शिक्षकों को छात्रों को केवल पाठ्यपुस्तकें ही नहीं, बल्कि कौशल-आधारित शिक्षा, समस्या-समाधान, टीम वर्क और मूल्य-आधारित शिक्षा, तथा ज्ञान के साथ-साथ सद्गुण भी सिखाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा के युग में छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करने वाली एक मजबूत पीढ़ी का निर्माण हो सके। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि पुरस्कार विजेता शिक्षक राज्य के ब्रांड एंबेसडर हैं।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने क्रांतिज्योति सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गौरव पुरस्कार वितरित किया। एनसीपीए के टाटा थिएटर में आयोजित इस समारोह में राज्य के 111 मेधावी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर, विधायक

जे.एम.अभ्यंकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मनीषा कायंदे, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शिक्षा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह सहित पुरस्कृत शिक्षक और उनके परिवारजन उपस्थित थे।

मंत्री नितेश राणे ने किया विहिप के परामर्श का समर्थन, कहा- गरबा आयोजन बन रहे लव जिहाद का केंद्र

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के उस परामर्श का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि गरबा आयोजकों को प्रतिभागियों के आधार कार्ड की जांच करनी चाहिए। राणे ने कहा कि नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा कार्यक्रम लव जिहाद के केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने एशिया कप के मैच पर आलोचना का जवाब देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधा।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के परामर्श का समर्थन करते हुए नितेश राणे ने कहा कि दक्षिणपंथी संगठन द्वारा की गई मांग में कुछ भी गलत नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इस्लाम मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। लव जिहाद के अलावा मुझे मुसलमानों के गरबा में भाग लेने के पीछे कोई और कारण नहीं दिखता। वे झूठी पहचान के साथ ऐसे आयोजनों में आते हैं और हमारी महिलाओं को परेशान करते हैं। लव जिहाद के मामले वहीं से शुरू होते हैं।

राणे ने आरोप लगाया, 'गरबा आयोजन लव जिहाद का केंद्र बनते जा रहे हैं। विहिप की मांग जायज है। अगर कोई अब भी गरबा में आता है तो उसका धर्म परिवर्तन कराइए क्योंकि वह ऐसे आयोजनों में शामिल होकर हिंदू बनने के लिए तैयार है। हम संगठनों से धर्म परिवर्तन प्रक्रिया की तैयारी करने को कहेंगे। आखिरकार एक समय में हम सभी हिंदू थे।'

संजय राउत पर साधा निशाना

महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री राणे ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दुबई में आपत्तिजनक इशारे किए। अगर किसी ने यहां ऐसा किया होता तो हम यह सुनिश्चित करते कि उन्हें इसका पछतावा हो। संजय राउत को हमें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभक्ति सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दिवंगत बालासाहेब ठाकरे एक ब्रांड थे, लेकिन उनके बेटे उद्धव इसे नष्ट करने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। अगर वह अन्य दलों के साथ गठबंधन करके ब्रांड को नष्ट करने पर तुले हैं तो हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।

नवरात्रि के पहले दिन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मध्य रेल कार्मिक विभाग की महिलाएं श्वेत परिधान में सजी हुई

सम्पादकीय

रूस की चेतावनी नई वैश्विक कूटनीतिक व्यवस्था का संकेत

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि भारत और चीन पर अमेरिका की टैरिफ धमकी बेअसर हो रही है और वाशिंगटन में दोनों प्राचीन सभ्यताओं के साथ ऐसी भाषा के प्रयोग की निरर्थकता को लेकर बहस चल पड़ी है।

भारत और चीन के खिलाफ जारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ युद्ध के खिलाफ रूस का खुलकर उतरना वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का उदाहरण है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दोनों देशों के पक्ष में खुलकर उतरना यह साबित करता है कि तीनों ही देश कम से कम आर्थिक विषयों के मामले में साथ आ रहे हैं। रूस का खुलकर भारत और चीन का साथ देना और अमेरिका का विरोध करना, वैश्विक दादागिरी वाली अमेरिकी कूटनीति को सीधी चुनौती कही जा सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन 17 सितंबर के दिन बधाई देकर एक तरह से दोनों देशों के रिश्तों में टैरिफ युद्ध के चलते आई तल्खी को कम करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन जमीनी स्तर पर अमेरिकी रुख में कोई बदलाव नहीं आने की वजह से वास्तविक हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे मौके पर सर्गेई लावरोव का बयान एक तरह से अमेरिका को चेतावनी हो सकता है।

भारत से अमेरिका को होने वाले आयात पर पचास प्रतिशत का टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका ने रूस से भारत द्वारा कच्चा तेल खरीदने को कारण बताया है। अमेरिका का कहना है कि भारत ऐसा करके रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग कर रहा है। हालांकि भारत इससे इनकार करता रहा है। भारत वैसे भी रूस से तेल खरीदने वाले देशों में निचले पायदान पर है। हां, भारत की रूस से नजदीकी रही है और वह बनी हुई है। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में रूस से भारत की नजदीकी दशकों से बनी हुई है। अमेरिका इससे चिढ़ता रहा है। हालांकि पिछले करीब दो दशकों से इसमें कमी आई है। इसकी वजह भारत का विशाल मध्य वर्गीय बाजार रहा है। जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन ट्रंप काल में आए टैरिफ बम के चलते इसमें गिरावट आ रही है।

सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को एक तरह से चेतावनी दी, अपने ही देश के मुख्य टीवी चैनल 1टीवी के कार्यक्रम 'द ग्रेट गेम' में उन्होंने कहा कि चीन और भारत प्राचीन सभ्यताएं हैं। उनसे इस तरह से बात करना कि या तो आप वह बंद कर दें जो हम नहीं चाहते या हम आप पर टैरिफ थोप देंगे, काम नहीं कर पाया।

सर्गेई ने इस कार्यक्रम में एक तरह चुटकी भी ली। उन्होंने अमेरिका के चीन और भारत से जारी रिश्तों को लेकर कहा कि चीन और भारत से जिस तरह का अमेरिकी संपर्क जारी है, वह दिखाता है कि अमेरिकी पक्ष वैश्विक कूटनीति में आ रहे बदलावों को समझ चुका है।

लावरोव ने अमेरिका के प्रति भारत और चीन की प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि अमेरिकी कदम से दोनों देशों को थोड़ी आर्थिक परेशानी जरूर हुई, क्योंकि दोनों ही देशों यानी चीन और भारत को नए बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोतों की तलाश करने और ज्यादा कीमत चुकाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस अमेरिकी रवैये का नैतिक और राजनीतिक विरोध भी हो रहा है।

लावरोव का यह कहना भी कि रूस पर नए प्रतिबंधों से कोई खतरा नहीं है, बहुत मानीखेज है। इसका मतलब यह है कि रूस कम से कम इस वक्त अमेरिकी दबवा में नहीं आने जा रहा। रूस पर वैसे ही बाइडन प्रशासन के जमाने से कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं, फिर भी रूस की सेहत और कूटनीति पर विशेष असर नहीं पड़ा है। ध्यान देने की बात यह है कि रूस, चीन और भारत की कुल जनसंख्या करीब तीन अरब है। जो वैश्विक जनसंख्या का करीब चालीस फीसद है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीनों देशों की अर्थव्यवस्था की सामूहिक भागीदारी करीब 32 प्रतिशत है। जाहिर है कि दुनिया में इनकी हिस्सेदारी अहम है। ऐसे में लावरोव का बयान एक तरह से अमेरिका को चुनौती ही है कि टैरिफ युद्ध खत्म हो या न हो, तीनों देश कम से कम अपनी आर्थिक चुनौतियों के सामने झुकने नहीं जा रहे।

चुनौती नहीं अवसर है ट्रंप की वीजा नीति, 'इंडियन ब्रेन' अब भारतीय कंपनियों में ऊर्जा लगाएँ और देश को आगे बढ़ाएँ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीज़ा को लेकर जो नया कदम उठाया है, वह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि वैश्विक प्रतिभा प्रवाह (उर्दैत ऊँतहू इत्दै) की दिशा बदलने वाला निर्णय सिद्ध हो सकता है। इस नीति के अंतर्गत हर वर्ष एच-1बी वीज़ा के लिए कंपनियों को एक लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) शुल्क देना होगा। यह राशि वर्तमान ढांचे की तुलना में कई गुना अधिक है और सीधे-सीधे उन कंपनियों पर बोझ डालेगी जो भारतीय और चीनी पेशेवरों पर निर्भर हैं।

दरअसल, ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। उनके अनुसार, जब अमेरिकी विश्वविद्यालय हर साल लाखों ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं तो कंपनियों को चाहिए कि वे उन्हीं को प्रशिक्षित करें और काम दें। यह कदम उनके 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ ही, 'प्रोजेक्ट फ़ायरवॉल' नामक नई पहल भी शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कंपनियों द्वारा वीज़ा दुरुपयोग पर रोक लगाना है। ट्रंप का कहना है कि अब तक एच-1बी वीज़ा का इस्तेमाल कंपनियां वेतन दबाने और अमेरिकी युवाओं की नौकरियां छीनने के लिए करती रही हैं। नई व्यवस्था में कंपनियों को भारी-भरकम शुल्क चुकाना होगा, जिससे वे विवश होकर स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देंगी।

हम आपको बता दें कि अमेरिका की अधिकांश टेक कंपनियां– जिनमें माइक्रोसॉफ्ट,

अमेज़न, मेटा और जेपी मॉर्गन जैसी दिग्गज शामिल हैं, वह भारतीय प्रतिभाओं पर काफी हद तक निर्भर हैं। केवल 2025 की पहली छमाही में ही अमेज़न और उसकी क्लाउड इकाई ने 12, 000 से अधिक एच-1बी वीज़ा मंज़ूर करवाए। देखा जाये तो भारत अकेले लगभग 71इ एच-1बी वीज़ा का लाभार्थी है। टेक कंपनियों का तर्क है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय इतनी मात्रा में कुशल इंजीनियर और प्रोग्रामर तैयार नहीं कर पा रहे जो उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें। इस स्थिति में भारतीय और अन्य एशियाई देशों के पेशेवर ही उनकी रीढ़ बने हुए हैं। अब ट्रंप के नये फैसले के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क बढ़ाने से अमेरिका अपनी नवाचार क्षमता खो सकता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी की होड़ में चीन से पिछड़ सकता है।

ट्रंप के फैसले का भारत पर क्या असर होगा यदि इसकी चर्चा करें तो आपको बता दें कि भारत इस नीति से सबसे अधिक प्रभावित होगा क्योंकि हर साल हजारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और वित्त विशेषज्ञ एच-1बी वीज़ा के जरिए अमेरिका जाते हैं। देखा जाये तो भारतीय युवाओं के लिए अमेरिकी नौकरी बाज़ार का दरवाज़ा सीमित हो जाएगा। इससे उनके सपनों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी कंपनियां अमेरिकी प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका भेजती रही हैं। नई नीति से इनकी लागत बढ़ेगी और प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ सकती है। साथ ही ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा असर यह हो सकता है कि अब तक जो उच्च कुशल प्रतिभा अमेरिका चली जाती थी, वह भारत में ही रहकर यहां की कंपनियों के लिए काम करेगी।

देखा जाये तो ट्रंप के फैसले को केवल नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत के लिए यह एक अवसर भी है। अब तक देखा गया है कि भारतीय मूल के कई दिग्गज अमेरिकी कंपनियों में शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं। जैसे सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, अजय बंगा आदि। यदि यही प्रतिभा भारत में रहकर देश की कंपनियों को आगे बढ़ाती तो भारत की वैश्विक स्थिति कहीं और होती। देखा जाये तो जब वैश्विक दरवाज़े सीमित होंगे तो भारत में स्टार्टअप कल्चर और मज़बूत हो सकता है। भारत सरकार के पास यह मौका है कि वह उच्च कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए टैक्स लाभ, बेहतर रिसर्च सुविधाएँ और आसान कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराए।

यदि भारत सरकार मजबूत ढांचा विकसित करे तो भारतीय युवाओं को अमेरिका जाने की आवश्यकता कम होगी। इसके अलावा, अमेरिका में काम करने वाली भारतीय प्रतिभा यदि भारत लौटती है तो सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिससे ये लोग यहां की कंपनियों को आगे बढ़ाएं। साथ ही, उच्च कौशल वाले पेशेवरों को टैक्स में छूट, आसान फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप का यह निर्णय अमेरिका के लिए शायद तत्कालिक राजनीतिक लाभ ला सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह कदम उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमज़ोर कर सकता है। दूसरी ओर, भारत को इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। अब तक कुशल भारतीय पेशेवरों का मस्तिष्क और मेहनत अमेरिकी कंपनियों के लिए संपत्ति बनता रहा है। यदि यही प्रतिभा भारत में रहकर भारतीय कंपनियों के लिए काम करे तो न केवल भारतीय उद्योग जगत बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति तेज़ हो सकती है।

आज भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों के शीर्ष पदों पर भारतीय बैठे हैं। अगर यही 'इंडियन ब्रेन' भारत की कंपनियों में अपनी ऊर्जा लगाएँ, तो इसका लाभ सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को मिलेगा। भारत सरकार को चाहिए कि इसे अवसर मानकर उच्च कौशल वाले पेशेवरों के लिए सुविधाजनक माहौल और प्रोत्साहन तैयार करे। बहरहाल, ट्रंप की यह नीति भारत के लिए मस्तिष्क पलायन को रोकने और प्रतिभा को देश में ही बनाए रखने का सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।

यूएन में किससे भिड़ गए ट्रंप, चीन भी देखता रह गया जीत गया बलूचिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में क्या-क्या हुआ?

पाकिस्तान और चीन को अमेरिका ने एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल, पाकिस्तान और उसका करीबी चीन बलूच लिबरेशन आर्मी और उसकी मजीद ब्रिगेड को संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी सूची में डालना चाहते थे। लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। पाकिस्तान और चीन चाहता था कि बीएलए को आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया जाए। लेकिन अमेरिका समेत फ्रांस और ब्रिटेन ने इससे हाथ खींच लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267वीं प्रतिबंध समिती के तहत पाकिस्तान और चीन ने एक प्रस्ताव रखा था। इसमें मांग की गई थी कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसका आत्मघाती दस्ता मजीद ब्रिगेड को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया जाए।

लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। अमेरिका के साथ फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान और चीन का साथ देने से इनकार कर दिया। जिसकी वजह से ये प्रस्ताव गिर गया। अमेरिका ने साफ कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी का अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से कोई संबंध नहीं है। हालांकि अमेरिका खुद बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन मानता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में 1267 सूची सिर्फ उन्हीं संगठनों के लिए है जिनका सीधा संबंध अलकायदा या आईएसआईएस से है। बता दें पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तार अहमद ने दावा किया था कि अफगानिस्तान में अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, तहरीक-ए-तालिबान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और बलूच लिबरेशन आर्मी के कम से कम 60 ठिकाने हैं। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1999 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव 1267 पारित किया, जिसके तहत ओसामा बिन लादेन और उसके साथियों को आतंकवादी घोषित किया गया और अल-कायदा, बिन लादेन या तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। यह अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हुआ। प्रस्ताव में आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने, आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और ओसामा बिन लादेन को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। प्रतिबंध लगाने से एक साल से भी कम समय पहले, बिन लादेन ने केन्या के नैरोबी और तंजानिया के दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की थी, जिसमें 224 लोग मारे गए थे और 4, 000 से ज़्यादा घायल हुए थे। प्रस्ताव 1267 ने प्रतिबंध सूची में व्यक्तियों या संस्थाओं को नामित करने और प्रतिबंध उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए एक यूएनएससी समिति की स्थापना की, जिसमें संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध शामिल थे। प्रारंभ में अल-कायदा और तालिबान से संबंधित होने के बावजूद, समिति के अधिदेश को 2015 में संकल्प 2253 के माध्यम से इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट (आईएसआईएल) को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था।

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह देश के लगभग 44इ भूभाग पर फैला है। हालाँकि इसकी अवस्थिति और प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल, की प्रचुरता इसे पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, लेकिन बलूचिस्तान की आबादी कम है और देश के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ के लोग गरीब हैं। 1948 में जब पूर्ववर्ती बलूच सरदारों को पाकिस्तान में विलय के लिए मजबूर किया गया था, तब से इस प्रांत ने खूनी विद्रोहों, क्रूर

सरकारी दमन और एक स्थायी बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन की एक श्रृंखला देखी है। अब तक, बलूचिस्तान में पाँच 'स्वतंत्रता संग्राम' हो चुके हैं, जो 1948, 1958-59, 1962-63, 1973-77 और 2005-06 के बाद लड़े गए।

पाकिस्तानी सरकार ने इन विद्रोहों से क्रूरता से निपटा है, और उसके सैनिकों पर अपहरण, यातना, मनमानी गिरफ़्तारी और फांसी की कई रिपोर्टें दर्ज की गई हैं। हालाँकि हताहतों की सही संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन रूढ़िवादी अनुमान भी यही कहते हैं कि सरकारी दमन में हज़ारों लोग मारे गए हैं। गैर-सरकारी संगठन वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के अनुसार, सिर्फ़ 2001 से 2017 के बीच लगभग 5, 228 बलूच लोग लापता हुए हैं।

बीएलए पाकिस्तान का एक उग्रवादी संगठन है, जिसका मकसद पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद कराना है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान में स्थानीय लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करती है। पाकिस्तान ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान पर इस संगठन को सपोर्ट करने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि भारत और अफगानिस्तान इस आरोप का विरोध करते रहे हैं। हालांकि बलूच लोग पाक के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन करते हैं।

मजीद ब्रिगेड बलूच लिबरेशन आर्मी के एक स्पेशल विंग है। इस विंग को खास तौर पर आत्मघाती हमलों के लिए भी तैयार किया गया है। इसमें शामिल होने वालों को कठिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मजीद ब्रिगेड का उद्देश्य खुद को समाप्त कर दुश्मन को खास संदेश देना है। इसमें आम तौर पर युवाओं की भर्ती होती है। इसकी स्थापना साल 2011 में हुई थी। इसका नाम बलूचिस्तान के दो सगे भाइयों लांगो और मजीद के नाम पर रखा गया। इसका नाम पूर्व प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के एक गार्ड के नाम पर रखा गया था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के संस्थापक की हत्या के प्रयास में मारा गया था। न्हें सम्मान देने के लिए ब्रिगेड का नाम मजीद ब्रिगेड रखा गया।

न्याय की रीढ़ पर वार : क्यों जरूरी है अधिवक्ता संरक्षण कानून

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की माँग उत्तर प्रदेश में लगातार तेज़ हो रही है। हापुड़ से वाराणसी तक हुई घटनाओं ने वकीलों की असुरक्षा को उजागर किया है। विधि आयोग और बार काउंसिल अपनी सिफ़ारिशें सरकार को दे चुके हैं। अब ज़रूरत है कि विधानमंडल तुरंत अधिनियम लागू कर न्यायपालिका की रीढ़ को मज़बूती दे।

लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में वकील समाज का अभिन्न हिस्सा है। अदालत की चौखट पर जब आम नागरिक न्याय की उम्मीद लेकर पहुँचता है, तो उसका सबसे बड़ा सहारा अधिवक्ता ही होता है। अधिवक्ता न केवल अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हैं, बल्कि न्यायपालिका और जनसाधारण के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करते हैं। किंतु दुखद है कि जो वर्ग कानून और व्यवस्था की रक्षा करता है, वही आज खुद असुरक्षित है।

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की शुरुआत जुलाई 2021 में हुई, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका मसौदा प्रस्तुत किया। इसमें अधिवक्ताओं को हिंसा, धमकी और उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा के ठोस प्रावधान रखे गए। 2022 में संसद की स्थायी समिति ने मसौदे की समीक्षा कर संशोधनों की सिफारिश की। इसके बाद मार्च 2023 में राजस्थान पहला राज्य बना जिसने यह अधिनियम पारित कर अधिवक्ताओं को सुरक्षा का कवच दिया और अन्य राज्यों में भी उम्मीद जगाई।

उत्तर प्रदेश में यह माँग 29 अगस्त 2023 की हापुड़ घटना के बाद और तीव्र हो गई। उस दिन पुलिस ने न्यायालय परिसर में निहत्थे अधिवक्ताओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। न्याय की रक्षा करने वाले स्वयं न्यायालय परिसर में ही अपमानित और घायल किए गए। यह दृश्य पूरे प्रदेश की बार एसोसिएशनों को झकझोर गया और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की माँग को और प्रबल बना दिया। इसके विरोध में 4 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने तीन-दिवसीय हड़ताल की घोषणा की और अदालतों में कामकाज ठप हो गया।

हापुड़ घटना के बाद 5 सितंबर 2023 को योगी सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का दायित्व था कि वह अधिवक्ताओं से सुझाव लेकर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करे और सरकार को अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने के संबंध में ठोस दिशा-निर्देश दे। 9 सितंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए एक न्यायिक समिति गठित की। समिति को 16 सितंबर से बैठकें शुरू करने का निर्देश दिया गया। अधिवक्ताओं ने पुलिस की बढ़ती दखलअंदाजी, मनमानी गिरफ्तारी और सुरक्षा की कमी की शिकायतें कीं। सितंबर के अंत तक 40 से अधिक शिकायतें मिलीं। अक्टूबर 2023 में अंतरिम रिपोर्ट में अधिवक्ताओं पर हमले को न्यायिक कार्यवाही में गंभीर बाधा बताया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार कर राज्य विधि आयोग को सौंपा। विधि आयोग ने नवंबर 2023 में अपनी सिफारिशें दीं, जिनमें अदालत परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, अधिवक्ताओं को सुरक्षित और पक्के चैंबर उपलब्ध कराने, सामूहिक बीमा योजना लागू करने और महामारी जैसी आपात परिस्थितियों में उन्हें न्यूनतम पंद्रह हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने का सुझाव शामिल था। आयोग ने यह भी कहा कि किसी अधिवक्ता की गिरफ्तारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न हो और गिरफ्तारी की स्थिति में 24 घंटे के भीतर संबंधित बार एसोसिएशन को सूचना दी जाए। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रारूप में अधिवक्ताओं पर हिंसा, धमकी, उत्पीड़न, संपत्ति का नुकसान और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर छह महीने से पाँच वर्ष तक की सजा और पचास हजार से दस लाख रुपये तक का जुर्माना होगा, जबकि पुनरावृत्ति की स्थिति में यह सजा दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। अदालत को पीड़ित अधिवक्ता को मुआवजा देने का अधिकार होगा।

लेकिन अधिवक्ता समाज को अपेक्षित परिणाम अब तक नहीं मिले। प्रयागराज में अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला की दिनदहाड़े हत्या ने यह संदेश दिया कि पेशेवर दायित्व निभाने वाले वकील भी असुरक्षित हैं। 17 सितंबर 2025 को वाराणसी जिला न्यायालय परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव हुआ, जिसमें उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग 70 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार किया और अदालतों का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। 19 सितंबर 2025 को चंदौली में अधिवक्ता कमला यादव की हत्या उनके ही भाई द्वारा कर दी गई और मुरादाबाद में एक महिला अधिवक्ता पर रासायनिक हमला हुआ। यह घटनाएँ इस तथ्य को पुष्ट करती हैं कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इन घटनाओं ने अधिवक्ता बिरादरी के आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुँचाया। 'हम अपने परिवार और बच्चों को हर रोज़ यह आश्वासन नहीं दे पा रहे कि हम सुरक्षित लौटेंगे। यह स्थिति अधिवक्ता बिरादरी के आत्मविश्वास को तोड़ रही है।' –वाराणसी के एक वरिष्ठ अधिवक्ता (स्थानीय अखबार से बातचीत, 2024)। युवा वकील और कानून पढ़ रहे छात्र-छात्राएँ अब सवाल करने लगे हैं कि क्या न्याय के लिए लड़ना उनके जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। जब अधिवक्ता भयभीत रहेंगे, तो कौन नागरिक का पक्ष निर्भीक होकर अदालत में रख पाएगा? 'अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल पेशेवर संरक्षण नहीं, बल्कि पूरे समाज के न्याय की सुरक्षा है।' –बार काउंसिल ऑफ यूपी, 2024। 17 सितंबर की वाराणसी घटना के बाद 20 सितंबर 2025 को विधान परिषद सदस्य अशुतोष सिन्हा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने की माँग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी ठोस कदम नहीं उठाती तो अधिवक्ता समाज का धैर्य टूट जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष परेश मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वाराणसी में पुलिस की कथित बर्बरता की मजिस्ट्रेटी जांच और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के त्वरित क्रियान्वयन की माँग की। आज स्थिति यह है कि बार काउंसिल और विधि आयोग दोनों अपनी रिपोर्ट और सुझाव सरकार को दे चुके हैं, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कर उदाहरण प्रस्तुत कर चुका है, किंतु उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं को अब भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली है। 'यदि अधिवक्ता सुरक्षित नहीं होंगे, तो न्यायपालिका की रीढ़ टूट जाएगी। यह केवल वकीलों का प्रश्न नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का प्रश्न है।' –उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़।

यहाँ मुद्दा केवल वकीलों की अभिरक्षा और सम्मानजनक वातावरण का नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की आत्मा का है। अधिवक्ता वह दीपक हैं जो अंधेरे में न्याय की लौ जलाए रखते हैं और समाज को अन्याय के अंधकार से मार्गदर्शन देते हैं। यदि यह दीपक डगमगा जाए, तो न केवल अधिवक्ताओं का अस्तित्व संकट में पड़ेगा, बल्कि नागरिकों के न्याय पाने का अधिकार भी कमजोर पड़ जाएगा। हापुड़ की लाठियाँ, प्रयागराज का खून, वाराणसी का टकराव और मुरादाबाद का अमानवीय हमला हमें यह चेतावनी दे रहे हैं कि अब देर की कोई गुंजाइश नहीं है। यह अधिनियम वकीलों के जीवन की ढाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सांस है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा और विधान परिषद को इस पर अब और मौन नहीं रहना चाहिए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर न्याय की ज्योति को बचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। यही समय है, यही अवसर है–यदि अभी नहीं तो शायद कभी नहीं।

घटी जीएसटी के स्लैब को लेकर फायदे बताएंगे भाजपाई

स्वदेशी सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे भाजपाई

प्रयागराज। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि 22 सितंबर को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर जीएसटी के नए स्लैब में जरूरत की सामग्री पर घटती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ में घटी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शुरुआत की गई जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि गण बाजार में निकलकर घटी हुई जीएसटी के फायदे बताएंगे और हर घर स्वदेशी घर-घर स्वदेशी अभियान के तहत लोगों को आने वाले पर्वों पर स्वदेशी सामान खरीदने का लोगों को प्रेरित करेंगे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी ,कार्यकर्ता, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के माध्यम से इस अभियान को गति देंगे।

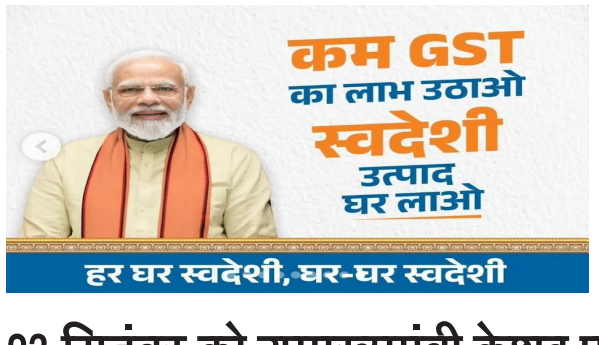

भारत ने दिखाया मार्ग : स्पेन में घोषित हुई सतत जलीय कृषि के लिए क्रांतिकारी बैक्टेरियोफेज़ चिकित्सा

प्रयागराज। जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है, जब भारतीय वैज्ञानिक डॉ. अजय कुमार सोनकर ने समुद्री मोती सीपियों की सर्जरी के बाद उन्हें एंटीबायोटिक-रहित उपचार से ठीक करने की विश्व की पहली तकनीक की घोषणा की। यह क्रांतिकारी खोज आज प्रतिष्ठित यूरोपियन एक्वाकल्चर सोसाइटी, एक्वाकल्चर 2025 सम्मेलन में वैलेंसिया, स्पेन में प्रस्तुत की गई।

डॉ. सोनकर ने अपने शोधपत्र 'मोती सीपों में शल्य चिकित्सा के बाद उपचार के लिए देशी समुद्री जीवाणुभोजी का उपयोगः एंटीबायोटिक दवाओं से एक स्थायी बदलाव' में यह अभिनव तकनीक प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समुद्री बैक्टेरियोफेज़ का उपयोग कर मोती सीपियों को सर्जिकल इम्प्लांटेशन के बाद स्वस्थ करने की प्रक्रिया बताई, जिससे एंटीबायोटिक की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है।

पिछले कई दशकों से, एंटीबायोटिक जलीय कृषि में आवश्यक माने जाते रहे हैं, विशेषकर मोती सीपियों की नाजुक सर्जरी के बाद। लेकिन इनके अत्यधिक प्रयोग से एंटीबायोटिक प्रतिरोध, पारिस्थितिकीय असंतुलन, और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

डॉ. सोनकर की बैक्टेरियोफेज़-आधारित चिकित्सा एक सतत और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, जो बैक्टीरिया पर प्राकृतिक नियंत्रण प्रदान करती है और समुद्री पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना मोतियों को सफलतापूर्वक स्वस्थ करती है। नियंत्रित अध्ययनों में इस पद्धति ने सर्जरी के बाद उपचार में असाधारण सफलता दिखाई है, जिससे सीपियों की जीवित रहने की दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। यह नवाचार भविष्य में मछली और अन्य शंख-शैवाल पालन जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो सकता है और एंटीबायोटिक पर वैश्विक निर्भरता घटा सकता है।

डॉ. सोनकर ने कहाः 'यह दुनिया में पहली बार है जब समुद्री सीपियों को सर्जरी के बाद बिना एंटीबायोटिक के ठीक करने की तकनीक सार्वजनिक की जा रही है। यह भारत की स्वदेशी विज्ञान शक्ति को दर्शाता है, जो वैश्विक जलीय कृषि के लिए एक सतत और स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।'

यह खोज जलीय कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और वैश्विक स्थिरता के

लिए भी महत्वपूर्ण है। एंटीबायोटिक का उपयोग घटाकर यह एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस जैसी गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का भी प्रत्यक्ष समर्थन करती है, जिनमें सतत खाद्य उत्पादन, जल-जीव संरक्षण और जिम्मेदार नवाचार शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने वैश्विक जलीय कृषि की दिशा बदलने में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। डॉ. सोनकर का कार्य इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार स्थानीय पारिस्थितिकियों में निहित वैज्ञानिक नवाचार पूरी दुनिया के लिए समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। यह न केवल खाद्य सुरक्षा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जन-स्वास्थ्य जैसे साझा वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में भारत के योगदान को भी रेखांकित करता है।

इस पहली सार्वजनिक घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, उद्योग जगत और नीतिनिर्माताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित होना तय है। यह तकनीक केवल मोती सीपियों की सर्जरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत करेगी, बैक्टेरियोफेज़-आधारित, एंटीबायोटिक-रहित जलीय कृषि का युग। डॉ. अजय कुमार सोनकर जलीय कृषि, मोती विज्ञान और समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात वैज्ञानिक हैं। उनका अनुसंधान पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का उदाहरण है, जिसने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त नवाचारों को जन्म दिया है जो स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाते हैं।

23 सितंबर को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध की अवशेषों को लेकर रुस के लिए करेंगे प्रस्थान

भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार कहा प्रयागराज के लिए गौरव का पल

प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पीएमओ इंडिया के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर 23 सितंबर को वायु सेवा के विशेषविमान से रूस के लिए प्रस्थान करेंगे।

भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता एवं महापौर गणेश केसरवानी ने खुशी जताते हुए कहा कि यह प्रयागराज के लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री और प्रयागराज के गौरव माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को भगवान बुद्ध जी की अवशेष कला-कृतियों को रूस ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ जो प्रयागराज के लिए गौरव का पल होगा इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री एवं पीएमओ इंडिया के प्रति हृदय से आभार है और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को हृदय से बधाई है।

मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रूस के कालमिकिया गणराज्य में भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय मंत्रालय भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों का प्रदर्शन करेगा इस प्रदर्शनी के माध्यम से हर एक देश में भारतीय आध्यात्मिक धरोहरों के संरक्षण संवर्धन और प्रचार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होगी। प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताने एवं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद को बधाई वालों में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता, कुंज बिहारी मिश्रा ,वरुण केसरवानी डॉक्टर शैलेश पांडे, राजेश केसरवानी, विवेक मिश्रा,पवन श्रीवास्तव,रमेश पासी,विवेक अग्रवाल, पार्षद किरन जायसवाल, प्रमोद मोदी, गिरजेश मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, विजय पटेल, विजय श्रीवास्तव, सुजीत कुशवाहा, अजय सिंह, अजय अग्रहरि, कमलेश कुमार, शत्रुघ्न जायसवाल आदि सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने बधाई दी।

नवरात्रि के पावन अवसर पर परमार्थ निकेतन में स्टेम सेल थैरेपी कैम्प का शुभारम्भ

नवरात्रि के प्रथम दिन उत्तराखंड़ आपदा पीड़ितों के लिये विशेष प्रार्थना व यज्ञ : स्वामी चिदानन्द सरस्वती

ऋषिकेश। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व, माँ दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का अवसर है। नौ दिवसीय इस महोत्सव को परमार्थ निकेतन में सेवा अनुष्ठान के रूप में समर्पित किया। नवरात्रि के अवसर पर मां हमें स्मरण कराती है कि जब-जब संसार में अंधकार, दुर्बलता और दुःख छाते हैं, तब शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा आशा और साहस का संचार करती हैं।

नवरात्रि के पावन अवसर पर, परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी और साध्वी भगवती सरस्वती जी के पावन सान्निध्य में स्टेम सेल थैरेपी कैंप का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। यह कैंप आधुनिक विज्ञान और सनातन संस्कृति की सेवा-परंपरा का संगम है। हमारी ऋषि परंपरा ने सदैव स्वास्थ्य को धर्म का प्रथम आधार माना है। शास्त्रों में कहा गया है शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् अर्थात् धर्म और कर्तव्य पालन के लिए स्वस्थ शरीर ही प्रथम साधन है। यही भाव इस कैंप की नींव में है।

नवरात्रि के इस पावन अवसर पर परमार्थ निकेतन में उत्तराखंड की आपदा पीड़ितों की आत्मा की शान्ति व पीड़ित परिवारों की सुख समृद्धि हेतु विशेष प्रार्थना की गयी। स्वामी जी ने कहा कि इस बार उत्तराखंड़ में प्राकृतिक आपदा ने जीवन और घर-परिवार को गहरी चोट पहुँचाई है। मां से प्रार्थना हैं कि प्रभावित परिवारों को शक्ति, साहस और संबल प्रदान करे तथा प्रदेश शीघ्र पुनर्निर्माण की राह पर अग्रसर हो।

स्वामी जी ने कहा कि आज नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के दिव्य दर्शन से जीवन में शांति, संतुलन और निर्मलता का संचार

होता है। यह पर्व केवल आराधना ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आंतरिक शुद्धि का भी अवसर है। वर्ष में दो बार आने वाली नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के साथ हमें शरीर, मन और आत्मा को सशक्त बनाने की प्रेरणा देती है।

नवरात्रि की नौ रातें हमारे जीवन के तीन गुणों की यात्रा हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। पहले तीन दिन माँ दुर्गा की उपासना तमोगुण का नाश करती है। अगले तीन दिन माँ लक्ष्मी की आराधना रजोगुण को संतुलित करती है। अंतिम तीन दिन माँ सरस्वती की पूजा सतोगुण को जागृत करती है। यह पर्व अज्ञान से ज्ञान की ओर, असंतुलन से सामंजस्य की ओर और दुर्बलता से शक्ति की ओर बढ़ने की आध्यात्मिक साधना है। आइए इस नवरात्रि शक्ति का पूजन करें, शांति की स्थापना करें, स्वयं को सशक्त करें और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं।

साध्वी भगवती सरस्वती जी ने कहा कि स्टेम सेल थैरेपी कैंप केवल चिकित्सा का केंद्र नहीं, बल्कि नयी आशा का दीपक है। आधुनिक विज्ञान की प्रगति और प्राचीन दर्शन की करुणा जब एक साथ आती है, तो समाज के लिए अमृत बन जाती है। इस कैंप का उद्देश्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को केवल उपचार देना नहीं, बल्कि जीवन में नयी ऊर्जा, नयी प्रेरणा और नयी दृष्टि देना भी है। कैंप के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बीमारी केवल शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की स्थिति से भी जुड़ी है इसलिए यहाँ उपचार केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दिशा में भी किया जाना जरूरी है।

डॉ. सुनीता राणा अग्रवाल, आर. अग्रवाल हॉस्पिटल्स एवं जीन रिसर्च फाउंडेशन, बैंगलोर और उनकी टीम ने इम्यून बूस्टर स्टेम सेल इंजेक्शन लगाकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेजा का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं का लिया जायजा

केन्द्र में साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक न पाये जाने पर जतायी नाराजगी, अभियान चलाकर व्यवस्था चुस्त-दूरूस्त बनाने के दिए निर्देश

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेजा, गौ-आश्रय स्थल कपूरी, निर्माणाधीन आईटीआई पथरपाल-कोरांव, निर्माणाधीन सड़क एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही पानी की टंकियों के निर्माण की प्रगति एवं जलापूर्ति की स्थिति का औचक निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित अधिकारियों को अवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेजा में मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिये जाने एवं चिकित्सालय में उपलब्ध आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की अद्यतन स्थिति का आंकलन किए जाने हेतु औचक निरीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई की व्यवस्था, चिकित्सकों और स्टॉफ की उपलब्धता एवं उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति, चिकित्सकीय जांच की मशीनों की उपलब्धता एवं संचालन, अभिलेखों की स्थिति, जनसामान्य हेतु उपलब्ध आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, महिला प्रसव वार्ड की स्थिति, एम्बुलेंस एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था न होने, शौचालयों नियमित सफाई न होने, चिकित्सालय परिसर में कूड़ा इक्ट्ठा होने एवं कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था अच्छी न होने, कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ-सफाई की नियमित एवं उचित व्यवस्था बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को चिकित्सालय परिसर में अभियान चलाकर साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयें मरीजों से उनका हालचाल जाना और उन्हें चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं है, दवाएं बाहर से तो नहीं मंगायी जा रही है, की जानकारी लिए जाने पर बताया गया कि दवाएं हॉस्पिटल से ही उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने दवा वितरण कक्ष का निरीक्षण करते हुए दवाओं के स्टॉक, उनकी एक्सपायरी डेट भी देखा एवं किन दवाओं की ज्यादा मांग है और उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी लिए जाने पर सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध पायी गयी। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में आने वाले लोगो के बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक केन्द्र का निरीक्षण करते हुए चिकित्सालय में नियुक्त सभी चिकित्सकों की ड्यूटी का विवरण बोर्ड लगाये जाने एवं पुरूष और महिला वार्ड कक्ष के बाहर वार्ड में भर्ती किए गए लोगो का विवरण चस्पा करने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली, जिसपर उन्हें बताया गया कि चिकित्सालय में पर्याप्त एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थिति पंजिका की जांच करते हुए सभी चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ को ड्यूटी के अनुसार समय से चिकित्सालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी मेजा, उपजिलाधिकारी कोरांव, जिला विकास अधिकारी जी0पी0 कुशवाहा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतोष कुमार, खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य सभी सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को जल जीवन मिशन के तहत तहसील मेजा अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौसिया दुबे, ग्राम पंचायत पथरताल एवं कोरांव तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत कपूरी में बनायी जा रही पानी की टंकी एवं वाटर सप्लाई की अद्यतन स्थिति का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया एवं सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। ग्राम पंचायत पौसिया दुबे में पानी की टंकी बनाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पाइप लाइन भी बिछाई जा चुकी है, किंतु अभी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। पानी की सप्लाई की टेस्टिंग का कार्य हो रहा है, जिसपर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को टेस्टिंग के कार्य को जल्द से जल्द कराते हुए टेस्टिंग में लिकेज की आ रही समस्याओं को दूर कराते हुए जल्द से जल्द पानी की सप्लाई शुरू कराये जाने के निर्देश दिए है। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने तहसील मेजा के ग्राम पंचायत पथरताल में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी का निरीक्षण किया। पानी की लाइन बिछाये जाने एवं पानी की टंकी एवं अन्य निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यो को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। तहसील कोराव अन्तर्गत ग्राम पंचायत कपूरी जोन 4 में इससे 05 ग्रामों में जल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण में कार्य प्रगति धीमे पाए जाने पर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए कहा है।

जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के टंकियों निरीक्षण के दौरान मौजूद किसानों के साथ बात करते हुए उनसे खाद, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सहित अन्य विषयों के बारे में जानकारी ली। किसानों के द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि यहां पर खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है तथा सिंचाई की कोई समस्या नहीं है। जिलाधिकारी ने उपस्थित किसानों को रासायनिक उर्वरको पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ जैविक कृषि अपनाने हेतु प्रेरित किया।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को कोरांव में प्रांतीय खण्ड-लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही कपुरी बेलहट सड़क का निरीक्षण किया और अवर अभियंता से सड़क एवं निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने कार्य की प्रगति में तेजी लाते हुए निर्धारित समय सीमा मार्च-2026 तक कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने कपूरी गौवंश आश्रय स्थल-कोरांव का निरीक्षण करते हुए गौ संरक्षण केन्द्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का जायजा लेते हुए वहां पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें चुस्त-दूरूस्त बनाये रखने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने गौशाला के प्रवेश द्वार के आकार को बढ़ाकर गेट लगाये जाने एवं गौशाला में एक बोर्ड लगाये जाने का निर्देश दिया, जिसमें सम्बंधित निराश्रित गौआश्रय स्थल का नाम, नियुक्त गौपालकों का नाम व अन्य विवरण उल्लिखित हो। उन्होंने निराश्रित गौवंशों की अधिक संख्या होने के दृष्टिगत एक अतिरिक्त शेड बनाये जाने तथा गौवंशों के लिए बनाये गये शेड के बाहर की तरफ स्थायी टेंट लगाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने गौशाला में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने, परिसर को साफ-सुथरा बनाये रखने, गौवंशों के बच्चों के लिए एक छोटी शेड और वहां पर कम ऊचाई के खाने की नांद बनाये जाने के लिए कहा है। उन्होंने चारे के स्टॉक एवं हरे चारे की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए हरे चारे की बुआई कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि हरे चारे, भूसा इत्यादि की कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि गौशाला में कहीं पर जल-भराव एवं कीचड़ की स्थिति न हो, इसके लिए नियमित साफ-सफाई होती रहे। जिलाधिकारी ने गौशाला के सुंदरीकरण एवं गौशाला परिसर में जल्दी ग्रोथ वाले छायादार पौधे लगाये जाने के लिए निर्देशित किया है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को तहसील कोरांव अन्तर्गत निर्माणाधीन आईटीआई पथरपाल-कोरांव का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।

निरीक्षण के दौरान आईटीआई का निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य का 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी के द्वारा कार्य की गुणवत्ता की जांच करते हुए अवशेष कार्यों के निर्माण की प्रगति एवं कब तक कार्य पूरा होगा, के बारे में जानकारी लिए जाने पर पता चला कि अवशेष कार्यों के लिए विगत छः माह से टेण्डर की कार्यवाही ही नहीं हुई है, जिसपर उन्होंने परियोजना प्रबंधक राजकीय निर्माण निगम पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं अवशेष कार्यों हेतु शीघ्र टेण्डर की कार्यवाही पूरी करते हुए अवशेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है।

प्राथमिक विद्यालय मटियारा में नवरात्रि पूजा

थरवई। विकासखंड सोराम के प्राथमिक विद्यालय मटियारा में सोमवार को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत श्रद्धा और उल्लास के साथ हुई। प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना विधि-विधान से संपन्न की गई।इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को नवरात्रि के महत्व और भारतीय संस्कृति की परंपराओं से जुड़ने का संदेश दिया गया। पूजा-अर्चना के उपरांत विद्यालय परिवार की ओर से महाप्रसाद का वितरण किया गया।कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका डॉ. रीना सिंह, मधुलिका सिंह, अखिलेंद्र, प्रियंका, शैल मिश्रा, सुप्रिया, अर्चना, आरती पटेल और वंदना मिश्रा सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।

आरएएफ 91 बटालियन में मां भगवती की पूजा-अर्चना

थरवई। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र स्थित आरएएफ 91 बटालियन डी कंपनी में सोमवार को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां भगवती की पूजा-अर्चना आचार्य पुरोहित अमित पाठक द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना एवं देवी की आराधना सम्पन्न कराई गई।इस अवसर पर उप कमांडेंट प्रमोद कुमार, सहायक कमांडेंट विवेक कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट महेंद्र कुमार, निरीक्षक अमित कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारीजवान कार्यक्रम मेंउपस्थित रहे। पूजा-अर्चना के दौरान पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और सभी ने मां भगवती से सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना

थरवई। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर श्रद्धा और उत्साह के साथ मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना एवं कलश स्थापना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी ग्रुप केंद्र धीरज कुमार ने विधि-विधान से वैदिक मंत्रऊच्चारण के बीचकलश स्थापना की गई इसके उपरांत मां दुर्गा की आराधना एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया।इस अवसर पर अधिकारियों एवं कार्मिकों ने सामूहिक रूप से मां दुर्गा से सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। आयोजन में प्रमुख रूप से कमांडेंट उदय प्रताप सिंह, कमांडेंट डॉ. बी.सी. यादव, उप कमांडेंट श्रीनिवास, उप कमांडेंट राकेश त्रिपाठी, उप कमांडेंट मंत्रालय के.के. झा, सहायक कमांडेंट अविनाश राय, सहायक कमांडेंट प्रभात पांडेय, शैलेश कुमार सिंह, महाराणा वीरेंद्र प्रताप सिंह, समय जैन सहित अन्य अधीनस्थ अधिकारीगण, जवान, महिला कार्मिक एवं परिवारजन मौजूद रहे।

श्रद्धा श्रीवास्तव प्राथमिक शिक्षक संघ की राष्ट्रीय काउंसलर बनी

प्रयागराज।उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश संगठन मंत्री श्रद्धा श्रीवास्तव को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का राष्ट्रीय काउंसलर नामित किया गया है। श्रद्धा श्रीवास्तव वर्तमान में विकासखंड सैदाबाद के प्राथमिक विद्यालय सिठौली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनके काउंसलर नियुक्त होने पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ प्रयागराज के शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है।जिला अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी जिला महामंत्री प्रशांत ओझा जिला उपाध्यक्ष देवव्रत द्विवेदी सहित जनपद प्रयागराज के विभिन्न ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी ने उनके चयन पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने कहा इससे जनपद प्रयागराज के शिक्षकों की बात ज्यादा मजबूती से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकेगी।

भिवंडी में पहला एक्यूपंक्चर चिकित्सा केंद्र शुरू

अब मिलेगा बिना दवा और बिना ऑपरेशन का इलाज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहरवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई पहल की गई है। स्वयं सिद्धि मित्र संघ कॉलेज ऑफ एक्यूपंक्चर थेरपी, भिवंडी की ओर से महाराष्ट्र आरोग्य शिक्षा मंत्रालय और महाराष्ट्र कौंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर से मान्यता प्राप्त भिवंडी का पहला एक्यूपंक्चर चिकित्सा केंद्र सोमवार को शुरू किया गया।उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ नगरसेवक बालाराम चौधरी प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन का कार्य पूर्व सभापति (शिक्षण विभाग) सुंदर नाईक ने किया, जबकि केंद्र के बोर्ड का शुभारंभ बालाराम चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे उपचार केंद्रों की और शाखाएं शहर में खोली जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र का संचालन सीए सुरेश जैन के मार्गदर्शन में होगा। आयोजकों ने बताया कि भिवंडी में पहली बार आधुनिक तकनीक से बिना दवा और बिना ऑपरेशन का इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस केंद्र पर गर्दन दर्द, पीठ दर्द, घुटने का दर्द, जमे हुए कंधे, पैरालिसिस, स्पोंडिलोसिस, स्लिप डिस्क, एड़ी का दर्द, सायटिका, सुनपन, झनझनाहट, अर्थराइटिस, सिरदर्द और माइग्रेन जैसी बीमारियों का निशुल्क उपचार किया जाएगा। ओपीडी का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। यह सेवा हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। इसका मुख्य केंद्र स्वयं सिद्धि शिक्षा संकुल, साई बाबा मंदिर के पास, कल्याण रोड, टेमघर में रखा गया है। उद्घाटन समारोह में सुंदर नाईक, रोहित चौधरी, संतोष पाटील, ट्रस्टी खांटेकर सर, ट्रस्टी सीए सुरेश जैन, सुरेश जाधव, डॉ. यासमीन अंसारी, डॉ. कल्पना, डॉ. मारिया जमीनदार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत कॉलेज के प्राध्यापकों ने शाल व पुष्पगुच्छ देकर किया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. महेश सोनी ने किया।

महिला वकील से6 लाख की मांग, पति और रिश्तेदारों पर मामला दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर में एक महिला वकील से उसके पति और परिजनों द्वारा मारपीट कर 6 लाख रुपये और एक एक्ट्रिका कार की मांग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला वकील ने पुलिस को बताया कि उनके पति अल्तमाश मेहमूद अहमद मोमिन (30), सासुर मेहमूद अहमद इलियास मोमिन (60) और ननद अलसबा और अल्शमा मेहमूद अहमद मोमिन मे उन्हें परेशान कर रहे थे।

घटना 8 दिसंबर 2024 की रात ढाई बजे से लेकर 19 जुलाई 2025 की रात साढ़े ग्यारह बजे के बीच ए विंग, हमदान कॉम्प्लेक्स, राजाजी नगर, कल्याण रोड, भिवंडी स्थित घर में घटी। आरोप है कि पति और परिजनों ने साजिशन पीड़िता पर 6 लाख रुपये और एक एक्ट्रिका कार लाने का दबाव बनाया। जब महिला ने इस पर आपत्ति जताई तो उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, पीड़िता और उसके मायके वालों को बदनाम करने तथा ट्रस्ट से जुड़ा स्कूल बंद कराने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने चारों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85,324(4),115(2),352,351(2),3(5) समेत हुंडाबली अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41(1)(अ) के तहत नोटिस जारी किया गया है। नाराज पीड़िता ने पुलिस से कहा कि लगातार मानसिक और शारीरिक छेड़छाड़ से उसकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

भिवंडी में फैक्ट्री से 90 हजार रूपये का औद्योगिक सामान चोरी

भिवंडी।शहर के औद्योगिक क्षेत्र में एक बार फिर बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। नारपोली पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार अज्ञात चोरों ने सांई गोविंद इंफ्रा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के परिसर से करीब 90 हजार रुपये का औद्योगिक सामान चुरा लिया।

शिकायतकर्ता मेहर प्रसाद मोगलल्ला (56) पुलिस को बताया कि 19 जनवरी की दोपहर दो बजे से लेकर 20 जनवरी की सुबह ग्यारह बजे के बीच बाम्बे टॉकीज के नजदीक खाड़ी, भिवंडी स्थित कंपनी के परिसर से यह चोरी हुई। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार चोरी गए सामान में एक्वा कंपनी के दो रिमोट, 90 एमएम का 60 मीटर लंबा रिमोट केबल, 25 एमएम की लाइटिंग केबल 200 मीटर लंबी, 40 एमएम की वेल्डिंग मशीन केबल 80 मीटर लंबी, 50 एमएम की वेल्डिंग केबल 50 मीटर लंबी और 25 एमएम की पावर कंडक्टर केबल की तीन कॉयलें शामिल हैं। सभी सामान की कीमत लगभग 90 हजार रुपये आंकी गई है। नारपोली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भिवंडी में दिनदहाड़े चैन स्नैचिंग

70 हजार की ज्वेलरी लूटकर फरार बदमाश

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी शहर में रविवार सुबह सरेआम चैन स्नैचिंग की वारदात ने नागरिकों में दहशत फैला दी है। जानकारी के अनुसार, 32 वर्षीय किरन दीपक म्हात्रे नामक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी दो अज्ञात बदमाशों ने उसे निशाना बनाया।

घटना पद्मानगर भाजी मार्केट के पास सुबह करीब 7 बजकर 20 मिनट पर घटी। पीड़ित के मुताबिक, काले रंग की मोटरसाइकिल पर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोक लिया। बाइक पर पीछे बैठे आरोपी ने झटके से उसके गले से सोने की चेन खींच ली और दोनों फरार हो गए।

पुलिस के अनुसार, लूटी गई सोने की चेन का वजन लगभग 25 ग्राम है और उसकी कीमत करीब 70,000 रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत भिवंडी शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में बताया गया है कि एक बदमाश की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है, शरीर मजबूत है, और वह काले रंग की फूलदार शर्ट व नीली टोपी पहने हुए था। वहीं दूसरा आरोपी भी लगभग इसी उम्र का, मजबूत कदकाठी वाला था और उसने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 309(4),3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है।

मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई से तीन जजों की बेंच ने खुद को अलग किया, अब चीफ जस्टिस सुनेंगे मामला

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के हालिया फैसले पर दायर याचिकाओं की सुनवाई से बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने खुद को अलग कर लिया। मामला उन आदेशों से जुड़ा है जिनमें मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र जारी कर उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले को ओबीसी संगठनों ने मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है।

कुल पांच याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें कुनबी सेना, महाराष्ट्र माली समाज महासंघ, अहीर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद मंडलिक और महाराष्ट्र नाभिक महामंडल शामिल हैं। उनका कहना है कि सरकार का फैसला तीन जातियों कुनबी, कुनबी मराठा और मराठा कुनबी के प्रमाणपत्र जारी करने के मानकों को बदल देता है। यह न केवल अस्पष्ट है बल्कि इससे अराजक स्थिति पैदा होगी।

जस्टिस संदीप पाटिल का बयान

याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप पाटिल ने कहा कि वे इन पर सुनवाई नहीं कर सकते। इसके बाद जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और संदीप पाटिल की बेंच ने मामले से खुद को अलग कर लिया। अब यह याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंकल की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए पेश की जाएंगी।

जारंगे की भूमिका और सरकार का कदम

सरकार का यह फैसला मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारंगे के आंदोलन के बाद लिया गया। जारंगे ने 29 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान में पांच दिन तक भूख हड़ताल की थी। इस दौरान उनके समर्थकों ने शहर के कई इलाकों में प्रदर्शन किया, जिससे बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि मुंबई ठप हो गई है।

सरकार का जीआर और समिति गठन

दो सितंबर को राज्य सरकार ने हैदराबाद गजेटियर पर आधारित एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया और समिति बनाने का ऐलान किया। यह समिति उन मराठा परिवारों की पहचान करेगी जो ऐतिहासिक रूप से कुनबी दर्ज हैं। ऐसे लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र मिलेगा और वे ओबीसी कोटे का लाभ ले सकेंगे।

ओबीसी समाज की नाराजगी

सरकार के इस कदम से ओबीसी समाज में बेचैनी है। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी किए गए जीआर के बाद ओबीसी संगठनों ने चिंता जताई है कि इससे उनकी आरक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह परिपत्र तरीके से मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल करने की कोशिश है, जो कानूनन गलत है। दरअसल, ओबीसी समुदाय का मानना है इस फैसले से उनके कोटे का आरक्षण बंट जाएगा.

मध्य रेल के महाप्रबंधक द्वारा हाल ही में न्यू डिजिटल असेट मैनेजमेंट सिस्टम सुगमरेल और रेल-अर्थ डिजिटल एप्लीकेशन्स का उद्घाटन किया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के महाप्रबंधक धर्म वीर मीना ने हाल ही में असेट मैनेजमेंट के लिए दो डिजिटल अप्लीकेशन्स (अनुप्रयोगों) - सुगमरेल और रेल-अर्थ - का उद्घाटन किया। इन अनुप्रयोगों को विद्युत विभाग द्वारा आंतरिक रूप से विकसित और लॉन्च किया गया है, जो मध्य रेल के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री अनूप कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में परिचालन के आधुनिकीकरण के लिए मध्य रेल के प्रयास का एक हिस्सा है। ये अप्लीकेशन पारंपरिक, पेपर -आधारित प्रक्रियाओं की जगह असेट मैनेजमेंट के लिए एक केंद्रीकृत, डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाएँगे, जिससे रेलवे नेटवर्क में संरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। प्रतीक गोस्वामी, अपर महाप्रबंधक, अनूप कुमार अग्रवाल, प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर, प्रमुख विभागाध्यक्ष और मध्य रेल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

संक्षिप्त विवरण

सुगमरेल और रेल अर्थ

सुगमरेलः लिफ्टऔर एस्केलेटरों के लिए सुगमरेल एक व्यापक असेट मैनेजमेंट प्रणाली है जिसे एस्केलेटर और लिफ्टों के रखरखाव और विफलता विश्लेषण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से पेपर रहित है, जो रखरखाव अनुसूचियों और निरीक्षण रिपोर्टों का डिजिटलीकरण करता है। सक्रिय रखरखावः यह प्रणाली बार-बार होने वाली विफलताओं और रखरखाव की नियत तिथियों के चूक जाने पर अलर्ट भेजती है, जिससे समय पर ध्यान और हाई कम्प्लायान्स (उच्च अनुपालन) सुनिश्चित होता है।

प्रदर्शन अंतर्दृष्टिः यह विस्तृत, असेट -वाइज कॉज -वाइज विफलता विश्लेषण प्रदान करता है। विफलताओं के बीच औसत समय और रखरखाव अनुपालन

दर जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतक का उपयोग असेट की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए किया जाता है।

केंद्रीकृत निगरानीः एक भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण प्रणाली, डिपो से लेकर मुख्यालय तक, सभी स्तरों पर असेट की स्थिति (महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य, स्वस्थ) की वास्तविक समय निगरानी की अनुमति देती है।

सुगमरेल एप्लिकेशन कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं

बेहतर यात्री अनुभवः सुगमरेल एस्केलेटर और लिफ्टों का सुचारू और निरंतर संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त अनुभव मिलता है।

कम खराबीः सुगमरेल के माध्यम से नियमित निगरानी संभावित समस्याओं की पहचान करने, खराबी की संभावना को कम करने और समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने में मदद करती है।

त्वरित समस्या निवारणः खराबी की स्थिति में, सुगमरेल एस्केलेटर और लिफ्टों का त्वरित समस्या निवारण और मरम्मत करता है, जिससे यात्रियों का डाउनटाइम और असुविधा कम होती है।

बेहतर रखरखावः यह एप्लिकेशन सक्रिय रखरखाव को बनाता है, जिससे निर्धारित मरम्मत संभव हो पाती है और अप्रत्याशित खराबी का जोखिम कम होता है।

बढ़ी हुई पहुँचः एस्केलेटर और लिफ्टों का विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करके, सुगमरेल सभी यात्रियों, विशेषकर गतिशीलता संबंधी चुनौतियों वाले यात्रियों के लिए पहुँच और समावेशिता को बढ़ावा देता है।

कुल मिलाकर, सुगमरेल एक अधिक कुशल, विश्वसनीय और यात्री-अनुकूल रेलवे प्रणाली में योगदान देता है।

रेल-अर्थः विद्युत अर्थिंग पिट्स के लिए रेल-अर्थ रेलवे के विद्युत अर्थिंग पिट्स के प्रबंधन को मैन्युअल से केंद्रीकृत, डेटा-परिचालित संचालन में बदल देता है। प्रत्येक पिट्स को एक विशिष्ट क्रमांक दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों को स्थान, जुड़ी हुई असेट और निरीक्षण इतिहास सहित जानकारी तक आसान पहुँच मिलती है। संरक्षा अलर्टः यह एप्लिकेशन अनहेल्दी पिट्स , अतिदेय निरीक्षणों और कभी जाँच न किए गए पिट्स के लिए तत्काल अलर्ट प्रदान करता है।

सुव्यवस्थित रिपोर्टिंगः यह अनिवार्य प्री-मानसून अनुपालन (कम्पलायेंस) रिपोर्ट सहित कुशल योजना और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे समय पर संरक्षा जाँच सुनिश्चित होती है।

बढ़ी हुई जवाबदेहीः यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म संरक्षा के प्रति अधिक जवाबदेही और सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

रेल अर्थ अर्थिंग के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं

बढ़ी हुई संरक्षाः रेल अर्थिंग जनता और कर्मचारियों को बिजली के झटके लगने के जोखिम को समाप्त करती है, जिससे एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित होता है।

जोखिम में कमीः उचित अर्थिंग कनेक्शन विद्युत दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं और लोगों को संभावित नुकसान से बचाते हैं।

विद्युत प्रणालियों की सुरक्षाः रेल अर्थिंग विद्युत प्रणालियों और उपकरणों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करती है, जिससे डाउनटाइम और रखरखाव लागत कम होती है।

संरक्षा मानकों का अनुपालनः रेल अर्थिंग को लागू करने से विद्युत सुरक्षा मानकों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है, जिससे संगठन के भीतर संरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

विद्युत झटकों की रोकथामः रेल अर्थिंग विद्युत धाराओं को ज़मीन तक पहुँचने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करती है, जिससे बिजली के झटकों से बचाव होता है और व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। रेल अर्थिंग को प्राथमिकता देकर, संगठन एक सुरक्षित और विश्वसनीय विद्युत अवसंरचना सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे लोगों और उपकरणों दोनों की सुरक्षा होती है। सुगमरेल और रेल-अर्थ, दोनों ही मध्य रेल के लिए परिचालन उत्कृष्टता, संरक्षा और विद्युत सामान्य असेट्स के रखरखाव हेतु अधिक विश्वसनीय यात्रा सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं।

लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं

पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि ट्रोलर्स, बिकाऊ मीडिया और पार्टी पर कब्ज़ा करने की बुरी मंशा रखने वाले लोग उनके खिलाफ निराधार अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड - मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाये जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुँचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा हैं .. मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी, न है और ना ही आगे रहेगी, न मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है, न राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है।

रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर कहा कि मेरे लिए मेरा आत्म - सम्मान, मेरे माता-पिता के प्रति सम्मान व् समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। आचार्य का यह स्पष्टीकरण कुछ रहस्यमयी ट्वीट्स के बाद आया है, जिनसे यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि मेडिकल स्नातक से गृहिणी बनीं आचार्य, जो पिछले साल के लोकसभा चुनावों में सारण से पार्टी की उम्मीदवार थीं, अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के प्रभाव से नाखुश थीं। मीडिया के एक हिस्से में ऐसी खबरें आई हैं कि सिंगापुर में रहने वाली आचार्या, जिनके एक्स पर दो लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं, लेकिन वे केवल तीन हैंडल्स को फ़ॉलो करती हैं, ने अपने पिता और छोटे भाई को अनफ़ॉलो कर दिया है।

दोनों सोशल मीडिया साइट पर उन्हें फ़ॉलो करते रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, राजद अपने संस्थापक अध्यक्ष के परिवार में कलह की तैयारी में लग रहा है। तेज प्रताप यादव इस साल की शुरुआत में प्रसाद द्वारा पार्टी से निकाले जाने के बाद से ही नाराज़ चल रहे हैं, वहीं आचार्य ने पिछले कुछ दिनों में अपने ट्वीट्स की श्रृंखला से कई लोगों को चौंका दिया है। 47 वर्षीया ने पिछले हफ़्ते अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, 'मैं एक बेटी और एक बहन होने के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करती रही हूँ और करती रहूँगी।

शहद उत्पादन में देश का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना बिहार

पटना। पिछले करीब 20 वर्षों में बिहार ने शहद के उत्पादन में काफी तेजी से प्रगति की है। 2005 से पूर्व जहां राज्य में काफी कम मात्रा में शहद का उत्पादन होता था वहीं अब यह बढ़ कर वर्ष 2023-24 में 18,030 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। बिहार देश में शहद का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। राज्य में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। शहद उत्पादन में बढ़ोत्तरी होने के कारण हजारों लोगों को रोजगार मिला है और इनके जीवन में खुशहाली आई है।

राज्य में सरकारी योजनाओं से मिले प्रोत्साहन, वनस्पतियों की विविधता, अनुकूल जलवायु एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण शहद का उत्पादन बढ़ा है। प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल से भी इसके उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। खासकर सरसों, लीची, सहजन, जामुन आदि फसलों के खेतों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलने से इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर लीची के बड़े-बड़े बागों के लिए जाने जाते हैं। लीची का शहद बिहार के सबसे लोकप्रिय शहद में से एक है।

बिहार में महागठबंधन की बिसात बिछाएगी कांग्रेस, CWC बैठक में तैयार होगी रणनीति

पटना। कांग्रेस पार्टी 24 सितंबर (बुधवार) को चुनावी राज्य बिहार में अपनी कार्यसमिति की बैठक आयोजित करने वाली है। पार्टी पटना स्थित अपने राज्य पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक आयोजित करेगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष राजेश राम, पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, राज्य विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सहित कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। पार्टी के राज्य प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीडब्ल्यूसी बैठक की जानकारी दी और बताया कि पार्टी कथित 'वोट चोरी' और राज्य में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, साथ ही राज्य में राष्ट्र की भी बात करेगी। बिहार में कई मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, बढ़ता अपराध, महिलाओं के खिलाफ़ अपराध, और ट्रंप के सामने युद्धविराम या आत्मसमर्पण।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस कार्यसमिति बिहार में इन मुद्दों पर चर्चा करेगी। 11 साल बाद भी मोदी इन समस्याओं का समाधान खोजने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, लोगों को यह समझना चाहिए। मोदी जी उस छात्र की तरह हैं जो पढ़ाई और मेहनत से नंबर लाने में विश्वास नहीं रखता। बल्कि वह उस छात्र की तरह हैं जो नकल करने की कोशिश करता है।' इससे पहले, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के तुरंत बाद आगामी बिहार चुनावों के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने का विश्वास जताया।

एएनआई से बात करते हुए, सिंह ने गठबंधन सहयोगियों के बीच एकता और भाजपा व नीतीश कुमार के गठबंधन को हराने के उनके साझा लक्ष्य पर ज़ोर दिया। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमुख चेहरे के रूप में भी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद यह जल्द ही हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है; सभी दल पूरी तरह आश्वस्त हैं... तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा चेहरा हैं... प्राथमिकता भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन को हराना है।

इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने संकेत दिया कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर के अंत में होने की उम्मीद है। हालाँकि, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।

पाक क्रिकेटर हारिश रऊफ की शर्मनाक हरकत! मैदान में उड़ाया ऑपरेशन सिंदूर का मजाक

आईएएफ पर इशारा कर भारतीय फैंस को उकसाया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। 21 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के मैच में, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों को विवादित 6-0 का इशारा करते हुए देखे गए। बाउंड्री के पास फील्डिंग करते हुए रऊफ द्वारा भारतीय प्रशंसकों को 6-0 का इशारा करते हुए कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। 6-0, पाकिस्तान के उस निराधार दावे का संदर्भ है जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद चार दिनों तक चली झड़प के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था।

भारत के खिलाफ मैच में, जिसमें पाकिस्तान 171 रनों के कुल स्कोर का बचाव करने में विफल रहने के बाद 6 विकेट से हार गया था, रऊफ ने चार ओवर फेंके और 26 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को तीन गेंदों पर शून्य पर आउट करके अपना विकेट खाता खोला और फिर संजू सैमसन का विकेट लिया। रन चेज़ के 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर अबरार अहमद ने सूर्या का कैच लपका, जबकि रऊफ़ ने सैमसन की रक्षापंक्ति को भेदते हुए 17 गेंदों में 13 रन भारत के कुल स्कोर में जोड़े।

बाउंड्री के पास क्षेत्ररक्षण करते समय, रऊफ़ को 'विराट कोहली' के नारे लगाने पड़े, क्योंकि प्रशंसक उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 2022 के मुकाबले की याद दिला रहे थे, जहाँ भारतीय बल्लेबाज़ ने आखिरी से पहले वाले ओवर में उन पर लगातार 2 छक्के जड़कर पासा पलट दिया था।

हालांकि, रऊफ़ ने इसके बाद जो किया वह बेहद उत्तेजक था। पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ ने प्रशंसकों की ओर '6-0' का इशारा किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के उन अपुष्ट दावों का ज़िक्र किया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य संघर्ष के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। 6-0 के इशारे के बाद, रऊफ़ ने विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की नकल करते हुए हाथ के इशारे भी किए।

दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की पूर्व संध्या पर सलमान अली आगा की टीम के एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान भी 6-0 के संकेत सामने आए। यह तब हुआ जब पाकिस्तानी टीम एक फुटबॉल मैच खेल रही थी, जिसमें एक टीम ने 6-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 6-0, 6-0... चिल्लाना शुरू किया, खासकर मैदान पर मौजूद भारतीय पत्रकारों की मौजूदगी में, उससे कई लोगों को समझ आ गया कि उनका इरादा कुछ और ही था। जहाँ पाकिस्तान और उसके कई पूर्व खिलाड़ी कहते हैं कि राजनीति और खेल एक-दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होने चाहिए, वहीं हारिस रऊफ़ जैसे खिलाड़ियों की मैदान पर की गई हरकतें सीमा पार के क्रिकेटरों की असल भावनाओं को कुछ और ही बयां करती हैं।

भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच की बात करें तो, एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की टीम ने पाकिस्तान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाती हैं तो भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में एक बार फिर आमने-सामने हो सकते हैं।

एशिया कप 2025 फाइनल हो सकता है भारत-पाक के बीच? बन रहा ऐसा समीकरण

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक नहीं बल्कि दो बार करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। पहले लीग स्टेज मुकाबले में और फिर सुपर-4 मुकाबले में 6 विकेट से पाकिस्तान को भारत ने परास्त किया है। इस हार के चलते पाकिस्तानी टीम की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, पाकिस्तानी टीम के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका है। बाकी दोनों मैच जीतकर वो फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को काफी मजबूत कर सकता है।

एशिया कप में सुपर-4 में पहुंचने वाली चारों टीमों को 3-3 मुकाबले खेलने हैं। अगर पाकिस्तान अब अगले दो सुपर- 4 मुकाबले जीत लेता है तो उसके चार अंक हो जाएंगे। ऐसे में अगर वो अंकतालिका में टॉप-2 में रहेगा, तभी फाइनल खेल पाएगा। वहीं भारतीय टीम के साथ भी यही स्थिति रहेगी। टीम इंडिया को भी खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए टॉप-2 में जगह बनानी होगी। फिलहाल, सुपर-4 में पहुंचने वाली चार टीमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है। वहीं बुधवार 24 सितंबर को भारत बांग्लादेश से टकराएगा। जबकि उसके बाद शुक्रवार को वो श्रीलंका से भिड़ेगा। अगर भारत इनमें से एक भी मैच जीतता है तो भी वो फाइनल में पहुंच सकता है। हालांकि, ऐसे में उसका रन रेट पर मामला अटक सकता है। अगर टीम इंडिया बाकी दोनों मैच जीतती है तो उसका फाइनल खेलना पूरी तरह तय रहेगा। तब नेट रन रेट की चिंता भारतीय टीम को नहीं करनी होगी। पाकिस्तान टीम अगर अपने अगले मुकाबले में 23 सितंबर को श्रीलंका से हार जाती है तो उसका बाहर होना लगभग तय हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश से जीतकर भी वो ज्यादातर 2 अंक ही जुटा पाएगा। अगर पाकिस्तान श्रीलंकाई टीम को हरा देता है तो फिर उसे फाइनल की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ जीत चाहिए होगी। श्रीलंका और बांग्लादेश भी फाइनल की रेस में बनी हुई हैं। श्रीलंका ने ग्रुप-बी में तीनों मैच जीते थे लेकिन सुपर-4 के पहले मैच में उसे बांग्लादेश ने हरा दिया। अगर बांग्लादेश के पास पहले से एक जीत है और उसके दो अंक हैं। भारत के पास भी दो अंक हैं और वो बेहतर नेट रनरेट के कारण पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे पर श्रीलंका और चौथे पर पाकिस्तान टीम है। एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान का फाइनल भी संभव है। अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतती है जबकि भारत भी अपने दोनों मैच जीतता है तो दोनों देश एशिया कप 2025 में तीसरी बार भिड़ेंगी। टीम इंडिया ने अगर एक मैच गंवाया जबकि पाकिस्तान टीम अपने बाकी मैच जीतती है तो भी दोनों के बीच फाइनल मुकाबला हो सकता है। हालांकि, ऐसे में नेट रन रेट भी अहम भूमिका निभाएगा।

बेशर्मी की हद : पहले आतंकी इशारे किए फिर कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता

पाकिस्तानी साहिबजादा फरहान ने दिया ये घिनौना बयान

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। बार-बार भारत के हाथों हार मिलने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते पाकिस्तान खिलाड़ी। एशिया कप 2025 में लगातार दूसरी बार हार झेलने के बाद भी बेशर्मी दिखा रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी। पाकिस्तान को भारत की धमाकेदार जीत का जश्न दुनियाभर में मौजूद हिन्दुस्तानी फैंस मना रहे हैं। भारतीयों के भीतर पाकिस्तान को हराने का जितनी खुशी है उतना ही गुस्सा भी है। पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान के गन स्टाइल सेलिब्रेशन पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है।

भारतीय फैंस का कहना है कि इस गन सेलिब्रेशन से साहिबजादा फरहान पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों को कुरेदना चाहते थे। मैच के दौरान ये घटिया हरकत करने वाले साहिबजादा फरहान अब घिनौना बयान देकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं।

वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साहिबजादा फरहान ने कहा कि, मुझे लगता है कि अगर आप छक्कों की बात करें तो आप भविष्य में ऐसा देखेंगे। और वह (जश्न) उस समय बस एक पल था। मैं 50 रन बनाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आयो कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मैंने वैसे ही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह भी नहीं है और बाकी आप जानते हैं। आपको जहां भी खेलना है आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए। जरूरी नहीं कि वह भारत ही हो। आपको हर टीम के खिलाफ आक्राम क्रिकेट खेलना चाहिए जैसा हमने आज खेला।

वहीं श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की आगे की क्या रणनीति होगी इस पर उन्होंने कहा कि टीम ने पहले पावरप्ले में काफी विकेट गंवाए थे। इसमें सुधार करना जरूरी है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पहले 6 ओवर्स में रन बनाए जाएं।

रिजर्व बैंक ने दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनियमित ऋण देने की गतिविधियों के कारण नयी दिल्ली स्थित दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण संचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। इस कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है। कंपनी ने ग्राहकों की सोर्सिंग, उनकी उचित जांच-पड़ताल, कर्ज का वितरण, कर्ज अदायगी, दिए गए कर्ज की वसूली और साथ ही केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) सत्यापन जैसी प्रमुख सेवाओं को आउटसोर्स करके मानदंडों का उल्लंघन किया है। किन कैश ऐप और 'दोलोन ऐप' (जेस्ट टॉप वन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लि.) और जेस्ट कैश ऐप (कंपनी का ऐप) सेवा प्रदाता हैं।

पहले क्रिकेट और अब फुटबॉल में पिटा पाकिस्तान भारत ने टी-सेलिब्रेशन की निकाली हवा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पहले भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर पस्त किया और अब फुटबॉल में भी भारत की अंडर-17 टीम ने पाकिस्तान को नहीं बख्शा। सोमवार, 22 सितंबर को कोलंबो में खेले गए सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप मुकाबले में भारत की टीम ने पाकिस्तान अंडर-17 टीम को हरा दिया। दल्लुलमुआन गांगटे, गुनलेइबा वांगकेइराक्पम और रहान अहमद के गोलों की बदलौत भारत को बेहतरीन जीत मिली। जिसके बाद ग्रुप बी में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की। इस मुकाबले में भी पाक खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों ने उकसाने की कोशिश की।

दरअसल, ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच रोमांचक रहा और पाकिस्तान के बराबरी के गोल के बाद हुए सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं। गांगटे ने 31वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई थी। लेकिन 12 मिनट बाद मोहम्मद अब्दुल्ला ने पेनल्टी से गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक अनोखा सेलिब्रेशन किया। अब्दुल्ला कॉर्नर पर जाकर बैठ गया और चाय पीने का इशारा किया।

वहीं कई लोगों ने इस सेलिब्रेशन को उकसाने वाला बताया लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने इस मुकाबले को जीतकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जवाब दिया।

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। 63वें मिनट में वांगकेइराक्पम ने बेहतरीन गोल दागकर भारत को फिर बढ़त दिला दी। हालांकि, सात मिनट बाद पाकिस्तान ने हमजा यासिर के गोल से फिर बराबरी की। लेकिन 73वें मिनट में अहमद के निर्णायक गोल ने भारत को जीत दिला दी।

रिया चक्रवर्ती ने जमानत मिलने के बाद जेल में किया था नागिन डांस, बताया क्लीन चिट मिलने पर कैसा था रिएक्शन

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ में काफी उथल-पुथल देखने को मिली। इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और 28 दिनों तक वहां रहना पड़ा। हालांकि, अब एक्ट्रेस को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। वहीं, हाल ही में 'जलेबी' एक्ट्रेस एनडीटीवी के एक इवेंट का हिस्सा बनीं, जहां उन्होंने जेल में बिताए अपने अनुभव के बारे में बात की और साथ ही यह भी बताया कि जब उन्हें क्लीन चिट मिली तो इस पर उनका रिएक्शन कैसा था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने जेल में नागिन डांस किया था।

इंटरव्यू में बात करते हुए रिया से पूछा गया कि अगर जेल में कोई फिल्म बन रही हो और वह खुद उसकी निर्देशक हों, तो वह किसे कास्ट करेंगी? इसके जवाब में अभिनेत्री ने कहा, 'मैं अपने किसी भी सहकर्मी के लिए ऐसी बदकिस्मती नहीं चाहूंगी। आपको कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल जिंदगी में कई हीरो और हीरोइन जेल गए और वापस आए हैं।'

बातें करते हुए रिया ने जेल के अनुभव भी शेयर किए। उन्होंने कहा, 'वहां आपको सब कुछ याद आता है कि आपके पास क्या था, जब आप सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि जेल में तो कुछ भी नहीं मिलता है। आप अपने माता-पिता को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वे आपसे पूछते रहते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं। जेल में आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। मुझे अपने परिवार की सबसे ज्यादा याद आती थी।'

एक्ट्रेस से जेल जाने के बाद क्या बदला इसके बारे में भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जेल जाने के बाद आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदल जाता है। आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इससे आपको डिप्रेशन जरूर होगा। आप लोगों की सोच से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, आप खाने की बहुत कद्र करने लगते हैं। घर का दाल-चावल भी पिज्जा जैसा नहीं लगता। आपको यह भी एहसास होता है कि दुनिया में आपके सिर्फ 3-4 दोस्त ही हैं, बाकी सब आपके दोस्त नहीं हैं।' बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने से पहले रिया चक्रवर्ती 28 दिनों तक जेल में रहीं। एक अभिनेत्री के तौर पर जेल में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया, 'लोगों ने मुझसे उनके लिए डांस करने को कहा। जमानत वाले दिन मैंने नागिन डांस किया। मैंने सोचा कि पता नहीं मैं उनसे अगली बार कब मिलूंगी और अगर मैं उन्हें खुशी के दो पल दे सकती हूं, तो क्यों न दूं? ऐसी अंडर-ट्रायल जेलों में ज्यादातर महिलाएं बेगुनाह और होपलेस होती हैं।'

सीबीआई द्वारा सभी आरोपों में क्लीन चिट मिलने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'उस दिन मेरे घर में सब रोए थे। मैंने अपने भाई को गले लगाया और फूट-फूट कर रो पड़ी। जब मैंने अपने माता-पिता को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि हम सब हमेशा के लिए बदल गए हैं। अब हम पहले जैसे बेफिक्र परिवार नहीं रहे। उस पल ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया।'

रिया ने आगे कहा, 'जब मुझे क्लीन चिट मिली, तो मैं बहुत खुश नहीं थी। असल में, मुझे पता था कि मेरा कोई बहुत करीबी चला गया है और इसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे अपने माता-पिता के लिए राहत मिली। वे समाज में रहते हैं और लगातार लोगों का सामना करते हैं। उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। मुझे लगा कि शायद अब वे थोड़ा और आजादी से घूम-फिर सकेंगे।'

नवरात्रि के पहले दिन 'मर्दानी 3' का ऐलान रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय बनकर लौटीं!

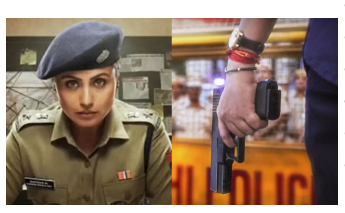

रानी मुखर्जी मर्दानी 3 में शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दो किस्तों की सफलता के बाद, निर्माताओं ने 27 फरवरी, 2026 को तीसरे भाग की रिलीज की पुष्टि की। नवरात्रि के शुभ अवसर पर, निर्माताओं ने मर्दानी 3 के नए पोस्टर का अनावरण किया। पोस्टर में रानी को हाथ में बंदूक पकड़े देखा जा सकता है। इस अनावरण के साथ, अभिनेत्री 'अच्छे और बुरे' के बीच एक महाकाव्य लड़ाई के लिए तैयार हो गई है। यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर मर्दानी 3 का नया पोस्टर शेयर किया है। इसे साझा करते हुए, निर्माताओं ने लिखा, नवरात्रि के शुभ दिन 1 पर, यहां बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी मुखर्जी अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण मामले की जांच करने के लिए मर्दानी 3 में

शीर्ष पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट रही हैं। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 27 फरवरी, 2026 को।' इससे पहले, एक आधिकारिक बयान में, अभिनेत्री ने खुलासा किया कि दर्शक मर्दानी 3 से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अप्रैल 2025 में मर्दानी 3 की शूटिंग शुरू कर रहे हैं! पुलिस की वर्दी पहनना और एक ऐसा किरदार निभाना हमेशा खास होता है जिसने मुझे हमेशा प्यार दिया है। मुझे मर्दानी 3 में इस साहसी पुलिस अधिकारी का किरदार फिर से निभाने पर गर्व है, जो उन सभी गुमनाम, बहादुर और आत्म-बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए हर दिन अथक परिश्रम करते हैं।' प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित, मर्दानी की पहली किस्त 2014 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। इसकी बड़ी सफलता के बाद, दूसरी किस्त 2019 में सिनेमाघरों में आई। दूसरे भाग का निर्देशन गोपी पुथ्रन ने किया था। 'मर्दानी' फ़िल्में - भारतीय सिनेमा में एकमात्र महिला-पुलिस प्रधान फ्रैंचाइज़ी - अपनी प्रभावशाली कहानियों से लगातार प्रशंसकों के दिलों पर राज कर रही हैं और समाज के लिए एक आँख खोलने वाली कहानी का काम कर रही हैं। पहली फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी, जबकि दूसरी 2019 में आई थी।

महाराष्ट्र शासन

कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय, दक्षिण मुंबई (विद्युत) सा.बां. विभाग, मुंबई

बांधकाम भवन, १ ला मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-०९.

मेल पत्ता: elsouthmumbai.ee@mahapwd.gov.in **दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२२००८४४८**

ई निविदा सुचना क्र. २३ सन २०२५-२६

कार्यकारी अभियंता दक्षिण मुंबई (विद्युत) विभाग, सा.बां. विभाग, मुंबई फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून विद्युत अनुज्ञापतीधाकर कंत्राटदाराकडून खालील कामाकरिता प्रारुप बी-१ नमून्यातील निविदा ई-निविदा प्रणालीव्दारे (ऑनलाईन) निविदा मागवित आहेत. निविदा कादपत्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्र्ेः//ईंर्पुही् दन.ग्ह येथून डाऊनलोड करण्यात यावी. तसेच निविदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार अधीक्षक अभियंता (वि), मुंबई प्रादेशिक विदयुत मंडळ, सा.बां. विभाग मुंबई यांना राखून ठेवला आहे. अट असलेली निविदा स्वीकारण्यात येणार नाही.

कामाचे नांव :- १) अंदाजपत्रक नं. ओडब्लु/सीईएसडी/०५०/२०५०/२०२५-२६ एल्फिस्टन टेक्निकल स्कूल परिसर, मुंबई येथील संविधान भवनमध्ये इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन, एचव्हीएसी सिस्टीम आणि संबंधित कामे करणे.

अंदाजित किंमत रुपये : २.३८,७८,४३१/- (दोन कोटी अडतीस लक्ष अठयाहत्तर हजार चारशे एकतीस फक्त)

कामाचे नांवः-२) अंदाज क्र. SR/C/HA/6313/2023-24- मुंबई, चर्चगेट, ए रोड, शासकीय लॉ कॉलेज, येथे (सिव्हिल स्ट्रक्चरल दुरुस्तीच्या कामांच्या समन्वयाने), इंटेलिजेंट ॲड्रेस करण्यायोग्य फायर डिटेक्शन आणि अलार्म सिस्टम आणि लेझर प्रोजेक्टर विज संच मांडणीचे नूतनीकरण करणे.

अंदाजित किंमत रुपये : २,२१,७६, २०६/- (दोन कोटी एकवीस लक्ष शहात्तर हजार दोनशे सहा फक्त)

ई- निविदा पूर्व बैठक वेळ व ठिकाणः- दिनांक २५.०९.२०२५ रोजी दुपारी १५:०० नंतर अधीक्षक अभियंता (वि), मुंबई प्रादेशिक विदयुत मंडळ, सा.बां. विभाग मुंबई.

कामाचे नांव :-३) अंदाजपत्रक क्र. अटल/शहर/एचए/१०३३/२०२५-२६ मित्सुभुशी हेवी इंडस्ट्रीजचे पूर्णतः सर्वसमावेशक देखभाल करार प्रदान करून मुख्य इमारत, मुंबई उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई येथे स्थापित व्हिआरएफ प्रकारची वातानुकूलन यंत्रणा (९०० एचपी) ३२ ड तीन वर्षांसाठी .(फेरनिविदा)

अंदाजित किंमत रुपये: १.६३.८९,०००/- (एक कोटी त्रैसष्ठ लक्ष एकोणव्वद हजार फक्त)

कामाचे नांव :-४) अंदाजपत्रक नं. एसआर/नविभ/ डीबी/५८१३/२०२५-२६ मुंबई विधानभवन, डोम इमारत येथील सिव्हिल वॉटरप्रूफिंग कामानुसार विद्यमान एअर हँडलिंग युनिट आणि दुसऱ्या मजल्यावरील टेरेसवर विघटन, स्थलांतर, बनावट आणि पुनर्स्थापना करणे.

अंदाजित किंमत रुपये: १,१२,९३,२६०/- (एक कोटी बारा लक्ष त्रैयानव हजार दोनशे एक)

ई-निविदा उपलब्ध कालावधीः २३.०९.२०२५ दुपारी १३.०० पासून ते दिनांक ०१.१०.२०२५ रोजी दुपारी १३.०० वाजेपर्यंत

निविदा उघडणे व ठिकाण : दिनांक ०३.१०.२०२५ रोजी दुपारी १४.०० नंतर अधीक्षक अभियंता (वि), मुंबई प्रादेशिक विदयुत मंडळ, सा.बां. विभाग मुंबई.

खालील संकेतस्थळावर ई-निविदांची सर्व माहिती उपलब्ध आहे.

१. https://mahatenders.gov.in

(सदर निविदासूचनेमध्ये काही बदल होत असल्यास वरील वेबसाईटवरती कळविण्यात येईल.)

२. कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई (विद्युत) विभाग, सा.बां. विभाग, मुंबई फोर्ट, मुंबई, कार्यालयातील सूचना फलक.

३. कामाच्या करारनाम्यात पोस्ट क्वॉलिफिकेशन क्रायटेरिया समाविष्ट केलेला आहे.

जा.क्र.-काअ/दमुविवि/नि.लि./५६६४/२०२५-२६

दिनांक :-१७.०९.२०२५

DGIPR/2025-26/2670

-sd-
कार्यकारी अभियंता
दक्षिण मुंबई (विद्युत) विभाग
सा.बां. विभाग, मुंबई

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

के.ई.एम. अस्पताल, परेल, मुंबई-400012

सं. केईएमएच 3258/एईएमई दिनांक 22.09.2025

ई-निविदा सूचना

यह एक ई-निविदा सूचना है। ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त निम्नलिखित कार्य के लिए 'वस्तु दर के आधार पर' ई-निविदा आमंत्रित करते हैं।

अ.क्र.	कार्य का नाम	बयाना राशि - रु.	बोली प्रारंभ तिथि एवं समय	बोली समाप्ति तिथि एवं समय
1	2	3	4	5
1	के.ई.एम.अस्पताल की एमएस बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर एंडोस्कोपी ओटी में अंडरडेक इंसुलेशन का कार्य। निविदा आईडी-2025_MCGM_1220866_1	10000/- @ 1%	22.09.2025 (17:00 बजे)	29.09.2025 (17:00 बजे)
	पात्रता मानदंड (पैकेट 'ए')	30.09.2025	17:30 बजे	
	तकनीकी बोली (पैकेट 'बी')	30.09.2025	17:45 बजे	
	व्यावसायिक बोली (पैकेट 'सी')	निर्धारित समय के अनुसार		

इच्छुक निविदाकर्ता निविदा के बारे में अधिक जानकारी के लिए (http://mahatender.gov.in) पर जाएँ। निविदाकर्ता ध्यान दें कि इस निविदा सूचना के संबंध में जारी किया गया कोई भी शुद्धिपत्र केवल (http://mahatender.gov.in) पोर्टल पर ही प्रकाशित किया जाएगा। स्थानीय समाचार पत्रों में कोई शुद्धिपत्र प्रकाशित नहीं किया जाएगा। निविदा दस्तावेज़ डाक द्वारा जारी या प्राप्त नहीं किए जाएँगे।

ए.ई.(एम और ई)
(के.ई.एम. अस्पताल)

पीआरओ/1692/विज्ञा./2025-26

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

केरल के कोची में आयुर्वेद दिवस मनाया गया

आयुर्वेद की ओर दुनियाँ का आकर्षण बढ़ा - डॉ जी एस तोमर

कोची। कोची में एमिल हेल्थ केयर के सौजन्य से आयुर्वेद दिवस-2025 मनाया गया । इस अवसर पर अनेक स्थानीय चिकित्सकों उपस्थित रहे । मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ जी एस तोमर ने बताया कि आयुर्वेद की बढ़ती हुई लोकप्रियता से प्रभावित होकर विश्व के अनेकों देश इसको मनाने के लिए उत्सुक हैं । इसी के दृष्टिगत हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष मंत्रालय के माध्यम से एक समिति गठित कर इसके लिए एक सुझाव माँगा । सौभाग्य से मैं भी उस समिति का सदस्य था । समिति ने इस आशय से कि आयुर्वेद दोष धातु मल एवं अग्नि के साम्य को ही आरोग्य मानता है । अतः 23 सितम्बर को जबकि दिन और रात बराबर होते हैं जिस कारण यह दिन इक्वीमॉक्स कहलाता है । इसी आधार पर यह तिथि आयुर्वेद दिवस के लिए सर्वोत्तम होगी । अतः 10 वाँ आयुर्वेद दिवस 23 सितम्बर को मनाया जा रहा है । पूर्व में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वन्तरि जयन्ती को मनाया जाता रहा है । इस दिवस का थीम 'आयुर्वेद जन

जन के लिए / आयुर्वेद पृथ्वी के कल्याण के लिए' है । अतः हमें इस विधा को आखरिी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है ।उन्होंने कहा कि आयुर्वेद न केवल स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन के लिए श्रेयस्कर है अपितु जीर्ण एवं असाध्य रोगों के लिए भी यह अत्यंत कारगर है । औषधियों की गुणवत्ता किसी भी चिकित्सा का आधार होती है । इस दिशा में एमिल का महत्वपूर्ण स्थान है । डॉ तोमर कहा कि हमारा दायित्व है कि हम आयुर्वेद औषधियों के साथ अपने रोजमर्रा के खानपान में प्रयुक्त मसालों एवं आसपास उपलब्ध जड़ीबूटियों के गुण धर्मों से जन जन को अवगत कराएँ एवं आयुर्वेदीय जीवनशैली को अपनाकर स्वस्थ एवं सशक्त भारत की संकल्पना में अपना योगदान दें । डॉ तोमर ने इस आयोजन के लिए एमिल के एमडी संचित शर्मा को धन्यवाद दिया ।

आयुर्वेद दिवस का आयोजन जी बी पंत संस्थान में - डॉ जी एस तोमर

प्रयागराज। विश्व आयुर्वेद मिशन एवं आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वावधान में धूतपापेश्वर के सहयोग से आयुर्वेद दिवस का आयोजन 23 सितम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झूँसी प्रयागराज में किया जा रहा है । इस अवसर पर 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' विषय पर एक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता जी बी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान की निदेशक डॉ अर्चना सिंह करेंगी । तथा विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ जी एस तोमर मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन देंगे । यह जानकारी विश्व आयुर्वेद मिशन के महासचिव डॉ धर्म प्रकाश आर्य ने दी है ।

तलाक के बाद पत्नी ने मांगे 5 करोड़ तो भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, दे डाली सख्त चेतावनी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक विवाह विच्छेद मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी चेतावनी दी, जब पत्नी ने एक साल पुरानी शादी तोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की। पीठ ने दोनों पक्षों को आगे की समझौता वार्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में लौटने का निर्देश दिया और आगाह किया कि अगर ऐसी मांगें जारी रहीं तो अदालत 'बेहद कठोर आदेश' जारी कर सकती है। पीठ ने गौर किया कि शादी को मुश्किल से एक साल ही हुआ था और पत्नी की ऊँची आर्थिक माँग पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पति के वकील से कहा, 'उसे वापस बुलाकर आप गलती कर रहे हैं। आप उसे अपने पास नहीं रख पाएँगे। सपने बहुत बड़े हैं। अगर आप उसे वापस बुलाते हैं, तो आप उसे वापस नहीं रख पाएँगे।

अदालत ने 5 करोड़ रुपये की मांग को अनुचित बताया और कहा कि ऐसा रुख प्रतिकूल आदेशों को आमंत्रित कर सकता है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि हम दोनों पक्षों को समझौते के लिए सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में वापस जाने का निर्देश देते हैं। हमें बताया गया है कि पत्नी ने विवाह विच्छेद के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की है। दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक जीवन लगभग एक वर्ष का ही है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने आगे कहा कि अगर पत्नी का रुख ऐसा ही रहा, तो हमें कुछ ऐसे आदेश देने पड़ सकते हैं जो उसे पसंद न आएँ। है ना? हम उम्मीद करते हैं कि पत्नी वाजिब माँग रखेगी और इस मुकदमे का अंत करेगी।

अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, अमेज़न में कार्यरत इंजीनियर पति ने कानूनी विवाद को समाप्त करने के लिए पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में 35 से 40 लाख रुपये की पेशकश की है। हालाँकि, पत्नी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को 5 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होने को कहा है। मध्यस्थता रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी।

सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल! मारपीट मामले में उन्नी मुकुंदन को कोर्ट ने किया तलब

चेन्नई। मार्को में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कक्कनाड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें उनके पूर्व पीआर मैनेजर विपिन कुमार द्वारा दायर मारपीट के मामले में 27 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है। यह समन पुलिस की उस जाँच के बाद जारी किया गया है जिसमें लगभग 10 मिनट के सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मोबाइल टावर लोकेशन डेटा सहित पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए थे। इससे पहले, कुछ मीडिया संस्थानों ने झूठा दावा किया था कि हमले या सीसीटीवी फुटेज का कोई सबूत नहीं है। हालाँकि, पुलिस जाँच में स्पष्ट सबूतों के साथ शिकायत की पुष्टि हुई।

आरोप पत्र धारा 115(2), 126(2), 296(बी), 351(2) और 324(4) के तहत दायर किया गया था, जो पीड़ित के फ्लैट परिसर में नुकसान पहुँचाने के इरादे से प्रवेश करने, पूर्वनियोजित हमला करने, गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने (विशेष रूप से पीड़ित के धूप के चश्मे को फेंकना और नष्ट करना) जैसे अपराधों से संबंधित है। ये आरोप ज़मानती हैं, और उन्नी द्वारा नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत ज़मानत के लिए आवेदन करने की उम्मीद है। इससे पहले, विपिन की शिकायत के जवाब में, उन्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि उन्होंने विपिन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और अगर यह साबित हो गया कि ऐसा नहीं है, तो वे अभिनय छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपिन उनके मैनेजर नहीं थे। कोच्चि में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्नी ने स्पष्ट किया कि कोई शारीरिक हमला नहीं हुआ था और विवाद को गलत तरीके से पेश किया गया था।

अभिनेता ने इस साल मई में कहा था यह मारपीट का मामला नहीं है। कोई शारीरिक हिंसा नहीं हुई। एक दोस्त होने के नाते, मैं बस विपिन से यह पूछना चाहता था कि वह मेरे बारे में नकारात्मक बातें क्यों कर रहा है। तीखी बहस के दौरान, मैंने उसका धूप का चश्मा फेंक दिया था।

कमल हासन का विजय को संदेशः भीड़ हमेशा वोटों में नहीं बदलती, हर नेता के लिए हकीकत

चेन्नई। मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) प्रमुख कमल हासन ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक रैलियों में उमड़ी भीड़ को वोट समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह सच्चाई तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय समेत सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होती है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक परामर्श बैठक के बाद चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए, हासन ने कहा कि यह निश्चित है कि सभी वोटों में तब्दील नहीं होंगे। यह सभी नेताओं पर लागू होता है।

जब उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि क्या उनकी टिप्पणी अभिनेता-राजनेता विजय के लिए थी, तो हासन ने स्पष्ट किया कि यह एक सामान्य टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि जब यह सभी नेताओं पर लागू होता है, तो हम विजय को कैसे बाहर कर सकते हैं? यह मुझ पर और भारत के हर नेता पर लागू होता है। आप भीड़ तो खींच सकते हैं, लेकिन वह सब वोटों में नहीं बदलेगी। टीवीके प्रमुख के लिए क्या उनके पास

कोई सलाह है, इस पर हासन ने कहा, 'सही रास्ते पर चलें, साहस के साथ आगे बढ़ें और लोगों का भला करें। यह मेरी सभी नेताओं से अपील है।' राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि आलोचना सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है, और यहाँ तक कि सिनेमा के महत्वाकांक्षी कलाकार भी इससे अछूते नहीं हैं। हासन की यह टिप्पणी डीएमके और अन्य दलों की इस आलोचना के बीच आई है कि विजय की रैलियों में भारी भीड़ का चुनावी समर्थन में तब्दील होना ज़रूरी नहीं है। हाल ही में, विजय ने एक रैली में अपने 'अनुयायियों से ईमानदार बने रहने, लोगों के लिए काम करने और सही तरह के नेतृत्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहने' का आग्रह किया था।

हासन, जिन्होंने 2018 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा, ने कहा कि अनुभव ने उन्हें दिखाया है कि 'भीड़ जुटाना केवल शुरुआत है, और निरंतर जमीनी स्तर पर काम ही अंततः वोटों का फैसला करेगा।' इस बीच, शनिवार को, टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे पर निशाना साधा और उन पर तमिलनाडु की प्रगति को रोकने का आरोप लगाया। तिरुवरुर में बोलते हुए, विजय ने राज्य के विकास की तुलना सत्तारूढ़ द्रमुक नेतृत्व द्वारा स्थिर छोड़े गए रथ से की।

यूपी में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध, FIR और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल करते हुए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार नेराज्य में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक स्थानों, आधिकारिक प्रारूपों और वाहनों से जाति-आधारित संदर्भों को हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक आधिकारिक आदेश में सभी राज्य विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गिरफ्तारी ज्ञापन, प्राथमिकी या किसी अन्य पुलिस दस्तावेज़ में जातियों का उल्लेख न हो। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि पुलिस नोटिसबोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड पर प्रदर्शित जाति-आधारित संदर्भों को भी हटा दिया जाए।

आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के माता-पिता के नाम का उपयोग 'पहचान' के लिए किया जा सकता है। इस आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के

लिए, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस नियमावली और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में भी संशोधन करेगी। राज्य सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड से जाति-आधारित संदर्भों को हटाने का आदेश तो दिया है, लेकिन कुछ छूट भी दी है। राज्य सरकार के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने वाले मामलों में छूट दी गई है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 सितंबर के अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख करने की प्रथा को रोकने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस प्रथा को कानूनी भ्रांति करार देते हुए कहा कि यह संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है और संवैधानिक लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों की जाति माली, पहाड़ी, राजपूत, ठाकुर, पंजाबी पाराशर और ब्राह्मण के रूप में दर्ज करने से कोई वैध या उचित उद्देश्य पूरा नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विभागीय जाँच की सिफ़ारिश करने या अधिकारी को संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक सरोकारों के बारे में जागरूक करने के बजाय, उनके आचरण का बचाव अस्पष्ट और असंतुलित आधारों पर किया गया।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की तलवार के बीच, रूस-ईरान का 8 परमाणु संयंत्रों पर बड़ा समझौता

तेहरान। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी वार्ता के लिए मास्को पहुँच गए हैं, ईरानी सरकारी मीडिया ने सोमवार को बताया। संयुक्त राष्ट्र इस बात पर विचार कर रहा है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाएँ या नहीं। 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तेहरान पर से प्रतिबंध स्थायी रूप से हटाने के प्रस्ताव के मसौदे को अस्वीकार कर दिया। इस कदम का रूस और चीन ने समर्थन किया था और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के प्रयासों का विरोध किया था।

यूरोपीय देश तेहरान पर विश्व शक्तियों के साथ 2015 में हुए उस समझौते का पालन न करने का आरोप लगाते हैं जिसका उद्देश्य उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था। ईरान ऐसी किसी भी मंशा से इनकार करता है और रूस का कहना है कि वह तेहरान के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार का समर्थन करता है। ईरान के उपराष्ट्रपति, इस्लामि ने ईरानी सरकारी मीडिया को बताया कि रूस की उनकी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें आठ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की योजना भी शामिल है, क्योंकि तेहरान 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है।

एस्लामी ने कहा कि अनुबंध पर बातचीत हो चुकी है और इस सप्ताह समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही हम परिचालन संबंधी कदम उठाएंगे। ईरान, जो उच्च मांग वाले महीनों के दौरान बिजली की कमी से जूझता है, के पास दक्षिणी शहर बुशहर में केवल एक चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसका निर्माण रूस द्वारा किया गया था और जिसकी क्षमता लगभग 1 गीगावाट है।

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले मंदिर में तोड़-फोड़, लूट के बाद तोड़ी 7 मूर्तियां

ढाका। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों की बढ़ती संख्या के बीच, स्थानीय मीडिया ने रविवार को बताया कि जमालपुर ज़िले के सरिषाबाड़ी उपजिला स्थित एक हिंदू मंदिर में एक बदमाश ने सात मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह घटना नगर पालिका के तारयापारा मंदिर में हुई, जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा से एक हफ़्ते पहले हुआ दूसरा हमला है। इस घटना की पुष्टि करते हुए, सरिषाबाड़ी पुलिस थाने के प्रभारी रशीदुल हसन ने कहा कि सूचना मिलते ही हम घटनास्थल पर पहुँचे। घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी है। यहां के जमालपुर जिले के सरिशाबारी उपजिला में एक हिंदू मंदिर में दुर्गोत्सव से पहले बनाई गई सात मूर्तियों को तोड़ दिया गया। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। बताया गया है कि यह घटना शनिवार रात नगर पालिका के तारयापारा मंदिर में हुई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव, दुर्गा पूजा उत्सव से एक हफ्ते पहले इस तरह का ये दूसरा हमला रिपोर्ट हुआ है। उधर, इस घटना की पुष्टि करते हुए, सरिशाबारी पुलिस थाने के प्रभारी रशीदुल हसन ने कहा, 'सूचना मिलने के बाद हम मौके पर पहुंचे। घटना के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।' उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पिछले हफ़्ते, बांग्लादेश की अवामी लीग ने अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार जहाँगीर आलम चौधरी की हिंदू धर्म के खिलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की थी। चौधरी ने कथित तौर पर हिंदू रीति-रिवाजों को शराब और नशीले पदार्थों का जमावड़ा बताया था। उनकी यह आपत्तिजनक टिप्पणी देश में आगामी दुर्गा पूजा समारोहों से पहले आई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से, बांग्लादेश हिंसा और चरम अराजकता की चपेट में है। अंतरिम सरकार को कट्टरपंथी और अतिवादी इस्लामी संगठनों को पनाह देने के लिए भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है।

38 साल पुरानी परमाणु संधि तोड़ने के बाद अब रूस ने किया ऐसा ऐलान, ट्रंप भी हो जाएंगे खुश

मास्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ अपनी परमाणु संधि की समाप्ति के बाद भी मास्को अगले एक साल तक परमाणु हथियार सीमाओं का पालन करता रहेगा। न्यू स्टार्ट संधि दोनों देशों के बीच अंतिम सक्रिय हथियार नियंत्रण समझौता है। रूसी सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए पुतिन ने चेतावनी दी कि इस समझौते को समाप्त करने से वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने आगे कहा कि रूस उम्मीद करता है कि वाशिंगटन भी ऐसा ही करेगा और संधि की सीमाओं का सम्मान करेगा।

2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा हस्ताक्षरित न्यू स्टार्ट संधि, दोनों परमाणु शक्तियों के बीच अंतिम सक्रिय हथियार नियंत्रण समझौता है। यह फरवरी 2011 में लागू हुआ और 2021 में इसे 5 फरवरी, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस समझौते का उद्देश्य सामरिक आक्रामक हथियारों को कम करना और सीमित करना था, जिससे वाशिंगटन और मॉस्को के बीच परमाणु संबंधों में स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। दोनों पक्ष 1,550 से अधिक सामरिक परमाणु हथियार तैनात नहीं कर सकते। संधि में तैनात अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों, पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु-सक्षम भारी बमवर्षकों की संख्या 700 तक सीमित है, जबकि तैनात और गैर-तैनात लांचरों की संयुक्त संख्या 800 तक सीमित है। इन प्रतिबंधों को साइट पर निरीक्षण, नियमित डेटा आदान-प्रदान और अधिसूचनाओं जैसे विस्तृत सत्यापन उपायों द्वारा समर्थित किया जाता है, जो सभी पारदर्शिता प्रदान करते हैं और आपसी विश्वास का निर्माण करते हैं।

वर्तमान में वाशिंगटन और मॉस्को के बीच शेष बचा अंतिम हथियार नियंत्रण समझौता है जो सामरिक परमाणु हथियारों और संबंधित वितरण प्रणालियों पर बाध्यकारी संख्यात्मक सीमाएँ लगाता है। यह रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने, पूर्वानुमान प्रदान करने और परमाणु वृद्धि के जोखिमों को कम करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना कर रहा है। फरवरी 2023 में, रूस ने निरीक्षण और रिपोर्टिंग में अपनी भागीदारी निलंबित कर दी, हालाँकि उसने कहा कि वह संख्यात्मक सीमाओं का सम्मान करना जारी रखेगा। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर यह संधि फरवरी 2026 में बिना किसी प्रतिस्थापन के समाप्त हो जाती है, तो दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियाँ दशकों में पहली बार अपने शस्त्रागार पर किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबंध के बिना रह जाएँगी। उनका तर्क है कि ऐसा परिणाम परमाणु जोखिम बढ़ा सकता है, अविश्वास को बढ़ा सकता है और वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर सकता है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)